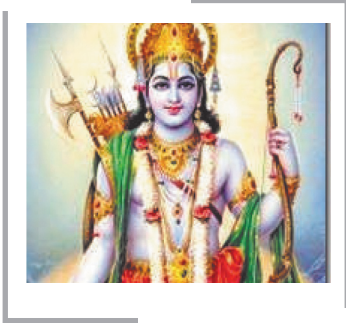




लोकसभा में बिना चर्चा के अधिकरण सुधार विधेयक पारित

कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित

नईदिल्ली। लोकसभा में मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण दो बार के स्थगन के बाद पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

दो बार के स्थगन के बाद जब दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू की तो विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गए और पिछले सप्ताह की तरह नारेबाजी करने लगे। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से हंगामा नहीं करने और सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया।इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल सत्र के पहले दिन से ही संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी यही मांग कर रहे हैं। उन्होंने



कहा कि गृह मंत्री छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर बयान देने के लिए तैयार हैं और सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के बाद श्री शाह के जवाब के लिए भी तैयार है।पीठासीन अधिकारी ने कहा कि जब संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि गृह मंत्री बयान देने के लिए तैयार हैं तो सभी सदस्यों को अपनी सीटों पर जाना चाहिए और सदन में व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब गृह मंत्री चर्चा का जवाब देने के लिए तैयार हैं और सरकार भी चर्चा चाहती तो सदन को चलने दिया जाना चाहिए। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को

अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 सदन में पारित कराने के लिए पेश करने को कहा। श्री मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह किसी अधिकरण के क्षेत्राधिकार में बदलाव नहीं करता, बल्कि पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। श्री जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए कई सदस्यों के नाम पुकारे, लेकिन हंगामे के कारण किसी सदस्य की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

इसके बाद उन्होंने विधेयक को सदन में पारित करने के लिए रखा और हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

बहिर्गमन के बीच बैंककार बही साक्ष्य विधेयक-2026 पर संसद की मुहर

नईदिल्ली। राज्य सभा ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के बहिर्गमन के बीच सोमवार को बैंककार बही साक्ष्य विधेयक-2026 को बिना किसी संशोधन के मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही बैंकों के बही-खातों के डिजिटल रिकार्ड को कानूनी मान्यता देने वाले इस इस विधेयक पर संसद की मुहर लग गयी है।इस विधेयक को लोक सभा में पिछले सप्ताह में पारित किया गया था। यह विधेयक अधिनियमित हो जाने के बाद बैंकों की बही को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किये जाने संबंधी 1891 के कानून की जगह लेगा। इस विधेयक में पुराने कानून के निरस्तीकरण का भी प्रावधान है। विधेयक पर संक्षिप्त बहस के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदस्यों द्वारा उठाये



गये मुद्दों का स्पष्टीकरण दिया। वित्त मंत्री के जवाब के बाद इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों के संबंध में प्रस्तुत संशोधनों को ध्वनिमत से निरस्त करते हुए सदन ने विधेयक पारित किये जाने के वित्त मंत्री के प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।इससे पहले एक के बाद एक कुछ विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा के लिए बुलाये जाने पर दिल्ली में युवाओं पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री जवाब की मांग उठाने का प्रयास किया और सदन में हंगामा होता रहा।उपसभापति हरिवंश ने विभिन्न नियमों का हवाला देते हुए उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। इसके विरोध में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गये थे।

राहुल को प्रयागराज नहीं, रांची जाना चाहिए था: रिजिजू

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रयागराज जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी को प्रयागराज की बजाय रांची जाना चाहिए था. रिजिजू ने रविवार कहा बड़ी गलती कर दी है, लेकिन गलतियाँ इसान से होती हैं. इससे पहले राहुल गांधी और किरेन रिजिजू के बीच शनिवार को महिला आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस देखने को मिली थी. दोनों के बीच बहस महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तावित परिसीमन से जोड़ने को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच हुई.बहस की शुरुआत तब हुई जब रिजिजू ने महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर राहुल गांधी के एक वीडियो पर टिप्पणी करते हुए उनसे महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने को कहा. इसके जवाब में राहुल गांधी ने सवाल किया कि महिला आरक्षण कानून को परिसीमन से जोड़ने की जरूरत क्यों है. राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज पहुंचे थे।



केसी वेणुगोपाल की शशि थरूर को चेतावनी

नईदिल्ली। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के सभी नेताओं को चेतावनी जारी की। यह चेतावनी तब दी गई जब पार्टी नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी के 'छात्रों की गुंज' आंदोलन की तुलना 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व वाले आंदोलन से की। वेणुगोपाल ने कहा कि सभी नेताओं को टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। थरूर के इस सुझाव पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कि राहुल गांधी का कार्यक्रम 'जेन-जी' के बीच उठना लोकप्रिय नहीं हुआ जितना सीजेपी के नेतृत्व वाले विरोध-प्रदर्शन, वेणुगोपाल ने कहा कि जहां तक मुझे पता है, मैंने उनका बयान केवल कुछ मीडिया चैनलों पर देखा है। मैं ठीक से सुन नहीं पाया कि उन्होंने असल में क्या कहा था। वेणुगोपाल ने कहा कि भले ही कांग्रेस के सदस्य हमेशा पार्टी के नियमों या अनुशासन का सख्ती से पालन न करते हों, लेकिन हमें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जिनसे सिर्फ भाजपा को फायदा हो या उन्हें खुश किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई राहुल गांधी में कोई कमी निकालता है।



भाजपा-अकाली दल गठबंधन अफवाह, सैनी ने किया खारिज

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की अटकलों को हरियाणा के मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी ने खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि पंजाब में भाजपा का गठबंधन किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता से है। सैनी ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी। सीएम सैनी यह बातें सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कही। बीते हफ्ते अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। सैनी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री और सुखबीर बादल की मुलाकात को भाजपा-अकाली गठबंधन से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों ने तो यह मानकर जश्न मनाया शुरू कर दिया।



आंखों के उपचार के लिए विदेश जा सकेंगे अभिषेक बनर्जी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत दी है। शीर्ष कोर्ट ने उन्हें आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते विदेश जाने की अनुमति दी। अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि वह एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने अपनी मेडिकल रिकॉर्ड्स जमा करने के लिए तैयार नहीं थे। कोर्ट का कहना था कि मेडिकल बोर्ड की विशेषज्ञ राय के आधार पर ही विदेश जाकर इलाज कराने की जरूरत का आकलन किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा था कि अभिषेक अपनी मेडिकल स्थिति की जांच के लिए अगले दिन कलकत्ता के एसएसकेएम अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने को तैयार नहीं थे। याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, आवेदक की ओर से दी गई दलील को देखते हुए कि वे कलकत्ता के एसएसकेएम अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं होंगे। यह कोर्ट मानती है कि इस याचिका के जरिए उठाया गया मुद्दा अब और लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।



रांची में जेपीएससी-जेएसएससी छात्रों का विधानसभा मार्च

रांची। सोमवार को रांची में हजारों नाराज छात्रों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और राज्य की पब्लिक सर्विस भर्ती प्रक्रिया में फैले भ्रष्टाचार के विरोध में झारखंड विधानसभा की ओर मार्च किया। यह विशाल विधानसभा घेराव लगातार 17वें दिन जारी भारी विरोध-प्रदर्शन का हिस्सा है; यह विरोध झारखंड पब्लिक सर्विस कमिशन (जेपीएससी) और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (जेएसएससी) की परीक्षाओं में पेपर लीक, रिश्ताखोरी और धांधली के बड़े पैमाने पर लगे आरोपों के कारण शुरू हुआ था। छात्र प्रदर्शनकारियों के सातवें और आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंचते ही पुलिस ने उनपर वाटर कैनन एक्शन शुरू कर दिया. ऐसे में छात्र पानी में जमकर डांस करने लगे और कहने लगे- और चलाओ, और चलाओ। विधानसभा घेराव मार्च के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जब सरकार ने नुकुले बैरिकेड लगाए, तो तबीयत ठीक न होने के बावजूद मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या यह पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन का बॉर्डर है? ये छात्र हैं। झारखंड विधानसभा की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों को पहले ओल्ड विधानसभा चौक के पास रोका गया था।



मोदी-योगी ने मिशन 2027 को सफल बनाने के लिए कसी कमर

नीरज कुमार दुबे

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले सप्ताहांत दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण और रणनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद योगी ने इसे 'सुशासन के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ने' के लिए प्रेरणा देने वाला बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार भेंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा।

दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के साथ ही उत्तर प्रदेश भाजपा ने संगठन को चुनावी मोड़ में डालते हुए नई नियुक्तियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी

ने छह संगठनात्मक क्षेत्रों और विभिन्न मोर्चों के प्रभारियों की घोषणा की है। नई टीम में करीब 60 फीसदी नए चेहरों को जगह दी गई है। साफ है कि भाजपा अब मिशन 2027 को केवल नारों तक सीमित रखने की बजाय बूथ से लेकर विधानसभा क्षेत्र तक संगठन को सक्रिय करने की तैयारी में है।

नई व्यवस्था में प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल को अवध, अभिजात मिश्रा को गोरखपुर, प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह को काशी और गीता शाक्य को बुज क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। राम प्रताप चौहान को पश्चिम तथा शंकर लाम्ही को कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। भाजपा ने इस बार सात की जगह आठ प्रदेश महामंत्री बनाए हैं। इसमें राजेश चौधरी को युवा मोर्चा, संजय राय को ओबीसी मोर्चा,

धर्मेंद्र सिंह को अनुसूचित मोर्चा, कामेश्वर सिंह को महिला मोर्चा, प्रियंका रावत को अनुसूचित जनजाति मोर्चा, देवेश कोरी को अल्पसंख्यक मोर्चा और शंकर गिरि को किसान मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई है।

यह बदलाव महज संगठनात्मक फेरबदल नहीं माना जा रहा। भाजपा की रणनीति साफ तौर पर हर सामाजिक वर्ग और हर क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ को चुनाव से पहले मजबूत करने की दिशाई दे रही है। मोर्चों और क्षेत्रीय समितियों के जरिए पार्टी अपने संदेश को गांव और बूथ तक पहुंचाने की तैयारी में है। नौ अगस्त से शुरू हुई तिरंगा यात्रा को भी इसी व्यापक जनसंपर्क अभियान की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। लखनऊ में आयोजित तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी



आदित्यनाथ की मौजूदगी ने भाजपा के चुनावी सक्रियता के संकेत और मजबूत कर दिए हैं।

संगठन के बाद अगला बड़ा सवाल उम्मीदवारों का है। पार्टी के भीतर विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों को लेकर शुरुआती मंथन जारी है। उनके कामकाज, क्षेत्र में सक्रियता और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता का आकलन सर्वे के जरिए

किए जाने की बात सामने आ रही है। यानी सिर्फ विधायक होना टिकट की गारंटी नहीं होगा। जिस विधायक के खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी होगी या जिसका प्रदर्शन कमजोर माना जाएगा, उसके स्थान पर नया चेहरा उतारने का विकल्प खुला रहेगा। भाजपा इस बार युवाओं को बड़ी संख्या में मौका देने की तैयारी में बताई जा रही है और इनमें महिलाओं की भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हो सकती है। यही वजह है कि आने वाले महीनों में कई मौजूदा विधायकों के टिकट पर संशय बना रह सकता है।इसी बीच भाजपा के भीतर एक और दिलचस्प सवाल उठ रहा है। एक-दो लोकसभा सांसद विधानसभा कराया जा रहा है। उनके कामकाज, क्षेत्र में सक्रियता और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता का आकलन सर्वे के जरिए

किए जाने की बात सामने आ रही है। यानी सिर्फ विधायक होना टिकट की गारंटी नहीं होगा। जिस विधायक के खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी होगी या जिसका प्रदर्शन कमजोर माना जाएगा, उसके स्थान पर नया चेहरा उतारने का विकल्प खुला रहेगा। भाजपा इस बार युवाओं को बड़ी संख्या में मौका देने की तैयारी में बताई जा रही है और इनमें महिलाओं की भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हो सकती है। यही वजह है कि आने वाले महीनों में कई मौजूदा विधायकों के टिकट पर संशय बना रह सकता है।इसी बीच भाजपा के भीतर एक और दिलचस्प सवाल उठ रहा है। एक-दो लोकसभा सांसद विधानसभा कराया जा रहा है। उनके कामकाज, क्षेत्र में सक्रियता और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता का आकलन सर्वे के जरिए

को सामने परिवारवाद से खुद को दूर रखने की चुनौती भी होगी। उम्मीदवारों के साथ ही एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का सवाल भी जल्द महत्वपूर्ण होने वाला है। भाजपा के सहयोगी दलों को मोटे तौर पर अपने संभावित हिस्से का अंदाजा पहले से है, लेकिन पिछली बार चुनाव बाद एनडीए में शामिल हुए सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के साथ सीटों को लेकर औपचारिक बातचीत अहम होगी। राजभर की पार्टी पहले ही ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी के संकेत देती रही है।एनडीए के दूसरे सहयोगी भी अपनी राजनीतिक ताकत के आधार पर अधिक सीटों के लिए मोलभाव करना चाह रहे हैं। ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती यह होगी कि सहयोगियों को पर्याप्त राजनीतिक स्पेस देते हुए अपनी सीटों

को सामने परिवारवाद से खुद को दूर रखने की चुनौती भी होगी। उम्मीदवारों के साथ ही एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का सवाल भी जल्द महत्वपूर्ण होने वाला है। भाजपा के सहयोगी दलों को मोटे तौर पर अपने संभावित हिस्से का अंदाजा पहले से है, लेकिन पिछली बार चुनाव बाद एनडीए में शामिल हुए सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के साथ सीटों को लेकर औपचारिक बातचीत अहम होगी। राजभर की पार्टी पहले ही ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी के संकेत देती रही है।एनडीए के दूसरे सहयोगी भी अपनी राजनीतिक ताकत के आधार पर अधिक सीटों के लिए मोलभाव करना चाह रहे हैं। ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती यह होगी कि सहयोगियों को पर्याप्त राजनीतिक स्पेस देते हुए अपनी सीटों

को सामने परिवारवाद से खुद को दूर रखने की चुनौती भी होगी। उम्मीदवारों के साथ ही एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का सवाल भी जल्द महत्वपूर्ण होने वाला है। भाजपा के सहयोगी दलों को मोटे तौर पर अपने संभावित हिस्से का अंदाजा पहले से है, लेकिन पिछली बार चुनाव बाद एनडीए में शामिल हुए सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के साथ सीटों को लेकर औपचारिक बातचीत अहम होगी। राजभर की पार्टी पहले ही ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी के संकेत देती रही है।एनडीए के दूसरे सहयोगी भी अपनी राजनीतिक ताकत के आधार पर अधिक सीटों के लिए मोलभाव करना चाह रहे हैं। ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती यह होगी कि सहयोगियों को पर्याप्त राजनीतिक स्पेस देते हुए अपनी सीटों

151 किमी लंबी कांवड़ यात्रा पर निकली विधायक भावना बोहरा

कबीरधाम। सावन का आज दूसरा सोमवार है। छत्तीसगढ़ के सभी शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी पंडरिया विधायक भावना बोहरा अमरकंटक से मां नर्मदा का जल लेकर भोरमदेव मंदिर और जलेश्वर महादेव मंदिर में अभिषेक के लिए निकल पड़ी हैं। करीब 115 किमी लंबी इस कांवड़ यात्रा को बीजेपी विधायक भावना बोहरा पूरा करेंगे। उनको इस यात्रा में करीब 500 कांवड़ भक्त शामिल हैं।

कांवड़ यात्रा के शुभारंभ के मौके पर पर बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, पत्थलगांव विधायक गोमती साय और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित बड़ी संख्या में समर्थक एवं श्रद्धालु अमरकंटक पहुंचे। ‘बोल बम’ और ‘हर-ह महादेव’ के जुधघोष के साथ कांवड़िए नाचते गाते यात्रा पर रवाना हुए। इस बार भी कवर्धा जिले से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़ यात्री अमरकंटक पहुंचे जल लेने के लिए पहुंचे हैं।

विधायक भावना बोहरा लगातार दूसरे वर्ष अमरकंटक से भोरमदेव तक यह कांवड़ यात्रा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा से जल लेकर 151 किलोमीटर

नर्मदा जल से करेंगी भोरमदेव का अभिषेक



की पदयात्रा कर जलेश्वर महादेव और भोरमदेव बाबा को जल अर्पित करना उनके लिए आस्था और संकल्प का विषय है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार यात्रा में अधिक संख्या में कांवड़िए शामिल हुए हैं।

बातचीत के दौरान विधायक भावना बोहरा ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य अपने विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धिऔर खुशहाली की कामना

करना है। बीजेपी विधायक ने कहा कि हाल ही में सनातन धर्म में वापसी करने वाले 15 बैगा आदिवासी महिला-पुरुष भी इस बार कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सभी लोग मां नर्मदा का जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे और खुशहाली की कामना करेंगे। 151 किलोमीटर की यह कांवड़ यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु जलेश्वर महादेव डोंगारिया और भोरमदेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव

का जलाभिषेक करेंगे। यह यात्रा करीब 151 किलोमीटर की है। कांवड़िए पैदल सफर तय करते हुए भोरमदेव और जलेश्वर महादेव डोंगारिया पहुंचेंगे, जहां मां नर्मदा के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। विधायक भावना बोहरा लगातार दूसरे वर्ष इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। भावना बोहरा ने कहा कि मां नर्मदा का जल लेकर भगवान भोलेनाथ के धाम तक पैदल पहुंचना उनके लिए केवल यात्रा नहीं, बल्कि आस्था और संकल्प का विषय है। उन्होंने बताया कि यात्रा के माध्यम से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की जा रही है। इतिहास

इस बार यात्रा में बैगा समाज के 15 महिला-पुरुषों की भागीदारी भी चर्चा में रही। हाल ही में सनातन धर्म में वापसी करने वाले इन लोगों ने भी मां नर्मदा का जल कांवड़ में उठाया और भगवान शिव के जलाभिषेक के संकल्प के साथ पदयात्रा शुरू की। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार यात्रा में अधिक संख्या में कांवड़ियों के शामिल होने का दावा किया गया है। अमरकंटक से शुरू हुई यह यात्रा कई पड़ावों से गुजरे हुए भोरमदेव पहुंचेगी।

बारिश का कहर: 24 घंटे बाद भी नहीं मिला उफनती नदी में डूबा नाबालिग

इधर नाला पार करना बुजुर्ग को पड़ा भारी!

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही/पिथौरा। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से मानसून एक्टिव है। अलग-अलग जिलों में लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। जलस्तर बढ़ने से नदी-नाले उफान पर है। नालों के ऊपर से तेज बहते पानी में भी लोग लापरवाही बरतना नहीं छोड़ रहे हैं। भौगोलिकसंदर्भ

महासमुंद जिले में लगातार बारिश के बीच बाघ नदी का बढ़ा जलस्तर जानलेवा साबित हुआ है। पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम कोड्डिमा में नदी में 17 वर्षीय नाबालिग हरिशंकर ठाकुर डूब गया। घटना का एनडीआरएफ टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नाबालिग का कोई सुगम नहीं मिल सका है।

जानकारी के मुताबिक, हरिशंकर ठाकुर नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर वह डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्व ऑपरेशन शुरू किया। घटना की सूचना मिलते ही पिथौरा पुलिस भी मौके पर पहुंच



गई। पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और एनडीआरएफ की टीम के साथ तलाश अभियान में समन्वय कर रही है। पिछले 24 घंटे से जवान लगातार नदी के अलग-अलग हिस्सों में सर्व ऑपरेशन चला रहे हैं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में लगातार जारी मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों और नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात बिगड़ने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नदी-नालों को पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला खोडडी थाना क्षेत्र के बड़ावनढांड-पीपरखुंटी मार्ग का है, जहां खूंटी नाले के तेज बहाव में एक बुजुर्ग बाइक सवार बहने से बाल-बाल बच गया।

जानकारी के अनुसार, बारिश के कारण नाले के रफते पर पानी का तेज बहाव था और दोनों ओर ग्रामीण जलस्तर घटने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक बुजुर्ग बाइक सवार वहां पहुंचा। ग्रामीणों ने उसे शोर मचाकर नाला पार करने से रोका, लेकिन वह नहीं माना और बाइक उफनते नाले में उतार दी। बीच में पहुंचते ही पानी के तेज थपेड़ों से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बुजुर्ग बाइक सहित पानी में गिर पड़ा। गनीमत रही कि बुजुर्ग और कड़ी तरह खुद को संभाला और किसी मशकत के बाद सुरक्षित बाहर निकल आया।

घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने इस पूरे हादसे का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने पर यहां स्थिति भयावह हो जाती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसे संवेदनशील नालों और रफतों पर पुलिस की तैनाती या संकेतक लगाए जाने की मांग की है।



राजनांदगांव। संस्कारधानी के 50 से ज्यादा वार्डों में जल्द ही आधारभूत व्यवस्थाओं की और दुरुस्त किया जाएगा। रिविwar को राजनांदगांव जिले के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने इसका ऐलान किया। अरुण साव ने कहा कि जल्द ही हमारा राजनांदगांव जिला आदर्श जिला बन जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के 51 वार्डों में सड़क, नाली, बिजली और पीने के पानी का बंदोबस्त और बढ़ाया जाए।

डिप्टी सीएम ने कहा कि जिले के विकास के लिए कई और मांगों भी सामने आई हैं, उन सभी मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शहर में 43 करोड़ 61 लाख 26 हजार की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें 15 करोड़ 92 लाख की लागत से बनने

वाला प्रदेश का सबसे बड़ा 2000 सीटर ऑडिटोरियम, जिसमें पार्किंग कॉरिडोर के साथ 2 हजार लोगों के एक साथ बैठकर भोजन करने की व्यवस्था होगी। भूमिपूजन के तहत शहर के सभी 51 वार्डों में सड़क, नाली, सीसी रोड, अंतर्लॉकिंग, विद्युतीकरण, प्रकाश व्यवस्था और पेयजल पाइपलाइन विस्तार सहित कई काम होंगे। 15वें वित्त आयोग की अनटाइड राशि से 12 करोड़ 9 लाख 44 हजार सड़क, नाली और विद्युतीकरण पर खर्च किए जाएंगे।

डिप्टी सीएम ने कहा कि अधोसंरचना मद से 11 करोड़ 57 लाख की लागत से सड़क, नाली, मुक्तधाम उम्यन और सामुदायिक भवन के काम कराए जाएंगे। 4 वार्डों में सड़क, नाली और सामुदायिक भवन के लिए 1 करोड़, जबकि 15वें वित्त आयोग

विश्व आदिवासी दिवस में सांसद संजय सिंह, हसंदेव जंगल कटाई पर मोदी सरकार को घेरा

गरियाबंद। विश्व आदिवासी दिवस पर गरियाबंद में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यक्रम के मंच से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि साढ़े दस करोड़ आदिवासी आबादी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक जज आदिवासी समाज से बने हैं। आज तक किसी आदिवासी को भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि

चार लाख पेड़ काटने की अनुमति दी गई है, जो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहलाता है। पेसा कानून के अनुसार पंचायत की अनुमति के बिना आदिवासी जमीन नहीं ली जा सकती। संजय सिंह ने नीट पेपर लोक मामले में भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेसा कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है।



हसदेव क्षेत्र में अडानी को साढ़े चार लाख पेड़ काटने की अनुमति दी गई है, जो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहलाता है। पेसा कानून के अनुसार पंचायत की अनुमति के बिना आदिवासी जमीन नहीं ली जा सकती। संजय सिंह ने नीट पेपर लोक मामले में भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेसा कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है।

प्रभावित हुए री-एग्जाम में करीब ढाई लाख छात्रों ने हिस्सा ही नहीं लिया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों से 25 दिन आमरण अनशन के बावजूद कोई बात नहीं की गई। संजय सिंह ने वे आदिवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और छत्तीसगढ़ तथा आदिवासियों की आवाज राज्यसभा में उठाएंगे।

आधुनिक तकनीक से जुड़कर आत्मनिर्भर व जागरूक बनेंगे वरिष्ठ नागरिक



भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्मल एजुकेशन (सीएसडीआई) ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। तकनीकी विश्वविद्यालय का उद्देश्य बुजुर्गों को आधुनिक तकनीक, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना है। इन कोर्सों के लिए 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सभी कक्षाएं चरक भवन (यूटीडी-4), सीएसवीटीयू से संचालित होंगी।

तकनीकी विश्वविद्यालय ने इस पहल के तहत तीन अलग-अलग 30 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स तैयार किए हैं। प्रत्येक कोर्स प्रतिदिन दो घंटे का होगा, जिससे वरिष्ठ नागरिक आसानी से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसमें डिजिटल छठी, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ी

जानकारी दी जाएगी। इस कोर्स की फीस 3000 रुपए निर्धारित की गई है। योगा एंड मेडिटेशन के तहत शारीरिक फिटनेस, मानसिक शांति और तनावमुक्त जीवन के लिए योग एवं ध्यान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कोर्स नि:शुल्क रहेगा।

वहीं भगवगीता के व्यावहारिक जीवन मूल्यों और आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित यह कोर्स भी नि:शुल्क होगा।

विश्वविद्यालय के अनुसार प्रत्येक कोर्स की अवधि 30 दिन होगी तथा सफल प्रतिभागियों को परीक्षा के बाद ग्रेड सहित सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। केवल वरिष्ठ नागरिक ही इन कोर्सों के लिए पात्र होंगे। किसी भी कोर्स की शुरुआत कम से कम 13 प्रतिभागियों के पंजीयन के बाद होगी। एक बार कक्षा शुरू होने के बाद फीस वापस नहीं होगी। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

कोरिया के प्रेमाशंकर महादेव मंदिर की जानिए अदभुत कथा

कोरिया। जिला मुख्यालय बैकतपुर से कुछ किमी दूर गेज नदी के किनारे शिवजी का एक अदभुत मंदिर है। शहरी आबादी से दूर बने इस मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पूजा पाठ के लिए पहुंचे। गेज नदी के तट पर बने प्रेमाशंकर महादेव मंदिर की महिमा को लेकर तरह-तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। स्थानीय लोग बताते हैं मंदिर का इतिहास करीब 105 साल पुराना है। मंदिर का निर्माण कोरिया रियासत के राजा के दीवान रघुवीर प्रसाद श्रीवास्तव ने अपनी दिवंगत पत्नी प्रेमाबाई की याद में कराया था। साल 1921 में 14 जनवरी को कोरिया रियासत के राजा के दीवान रघुवीर प्रसाद श्रीवास्तव ने अपनी दिवंगत पत्नी प्रेमाबाई की याद में इस मंदिर का निर्माण कराया। पत्नी की स्मृति को हमेशा जीवित रखने के उद्देश्य से मंदिर परिसर का नाम प्रेमाबाग रखा गया, जबकि यहां स्थापित शिवलिंग को प्रेमाशंकर महादेव के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ-साथ वैवाहिक प्रेम और समर्पण की मिसाल के रूप में भी अपनी अलग पहचान रखता है।

विश्व आदिवासी दिवस पर सक्ती कलेक्टर की बड़ी घोषणा

सक्ती। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक बेहद सराहनीय और अनोखी पहल देखने को मिली है। सक्ती के कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने आदिवासी समाज के कल्याण के लिए एक बड़ी घोषणा की है।कलेक्टर ने समाज के प्रमुखों को सलाह दी है कि अगर उनकी कोई आधिकारिक समिति नहीं बनी है, तो वे जल्द से जल्द उसका रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) कराएं। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि वे हर साल अपनी निजी तनख्वाह से 10 हजार रुपए समाज की कल्याण समिति को दान करेंगे। कलेक्टर ने बताया कि वे खुद एक आदिवासी परिवार से आते हैं और आज भगवान की कृपा से इस योग्य और सरकारी पद पर हैं, इसलिए समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना उनका कर्तव्य है। कलेक्टर की इस भावुक और प्रेरणादायक घोषणा के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों के साथ इसका स्वागत किया। मंच पर मौजूद जिले के एसपी प्रफुल्ल ठाकुर सहित सैकड़ों अन्य लोगों ने भी इस नेक काम में अपना पूरा समर्थन और सहयोग देने की बात कही।

धमतरी में बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार में बवाल

धमतरी। वनांचल जिले धमतरी में एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। जिले के रांवा कुर्रा गांव में 80 वर्षीय सोनबती यादव की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर गांव में विरोध शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि सोनबती यादव ने एक वर्ष पहले ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसके बाद उनको मौत के पश्चात अंतिम संस्कार किस रीति-रिवाज से किया जाए, इसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। महिला की मौत की जानकारी मिलने के बाद हिन्दू जागरण मंच के कार्यकर्ता और कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने महिला के अंतिम संस्कार को लेकर आपत्ति जताई और विरोध दर्ज कराया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और माहौल गरमा गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद भखारा थाना पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को संभालने के साथ ही दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया।

खदान में डूबा युवक डीप डाइविंग टीम ने किया रेस्क्यू

बेमेतरा। बेरला थाना के ग्राम चंडी भाटा में बंद पड़े पत्थर खदान में डूबने से रायपुर के युवक की मौत हो गई। मृतक युवक का नाम हर्ष दास था और वो नहाने के लिए खदान के गहरे पानी में उतरा था। युवक को गहराई का अंदाजा नहीं मिला और वो डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और डेड बॉडी को पानी के नीचे से रेस्क्यू किया। जिस जगह से युवक का शव मिला वहां पर पानी की गहराई करीब 30 फीट है। पुलिस कंट्रोल रूम दुर्ग के मुताबिक हादसा शाम 6 बजे के करीब हुआ। मृतक युवक हर्ष दास रायपुर के भनपुरी का रहने वाला था। युवक अपने तीन दोस्तों के साथ चंडी भाटा आया था नहाने के लिए पानी में उतरा था। मृतक के दोस्तों की सच्चना पर पुलिस ने रेस्क्य अभियान चलाया। देर शाम तक युवक की तलाश जारी रही जिसके बाद आज सुबह शव को बाहर निकाला जा सका। मौके पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया की गंभीरता को देखते हुए जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी रावटे के निर्देश पर तुरंत रेस्क्यू टीम एक्टिव किया ।

खाने-पानी की तलाश में भालू पहुंचा रिहायशी इलाके तक

कांकर। मरवाही और कांकर के जंगल में बड़ी संख्या में भालू रहते हैं। फलों के पेड़ और शहद की भारी मात्रा में उपलब्धता के चलते भालूओं का यह सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। लेकिन जिस तेजी से फलों के पेड़ कम हो रहे हैं और शहद के छत्ते घटने लगे हैं, उससे भालू अब खाने पीने की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। कई बार इनका सामाना ईसानों से भी हो जाता है। बीते दिनों ही भालू ने भाई –बहन को मार डाला था। वन विभाग की टीम लगातार लोगों को सचेत करते रहती है कि वो जंगली जीवों को छेड़े नहीं और खतरा होने पर वन विभाग को तत्काल सूचना दें। रिविwar को नरहपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम कुसुमपानी में जंगल से भटककर गांव के करीब पहुंचा भालू का बच्चा कुएं में जा गिरा। गांव वालों ने जब कुएं से किसी जानवर के शोर मचाने की आवाज सुनी तो वो मौके पर पहुंचे। कुएं में जब लोगों ने झांककर देखा तो पाया कि एक भालू कुएं में गिरा है। कुएं में पानी कम होने की वजह से भालू को न तो चोटा आई न ही वो पानी में डूबा ।

भखारा के शासकीय आईटीआई परिसर में आकार ले रहा ‘ऑपरेशन सिंदूर उद्यान’

धमतरी। शासकीय आईटीआई परिसर भखारा में पर्यावरण वानिकी मद से लगभग 31 लाख रुपए की लागत से विकसित किया गया ‘ऑपरेशन सिंदूर उद्यान’ अब अपने स्वरूप में निखरने लगा है। उद्यान में लगाए गए विभिन्न प्रजातियों के पौधे धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और परिसर में हरियाली की सुंदर छटा दिखाई देने लगी है। कभी अपेक्षाकृत खाली नजर आने वाला परिसर अब हरे-भरे वातावरण और व्यवस्थित पौधरोपण के कारण आकर्षण का केंद्र बन रहा है।

इस उद्यान का निर्माण पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र के विस्तार तथा नागरिकों और



विद्यार्थियों को स्वच्छ एवं प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है। उद्यान में औषधीय, फलदार एवं

बिताने तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उपयोगी स्थल भी बनेगा। उल्लेखनीय है कि शासकीय आईटीआई भखारा

हरियाली से बढ़ी परिसर की खूबसूरती, औषधीय एवं फलदार पौधों से पर्यावरण संरक्षण को मिल रहा बढ़ावा

परिसर में लगभग 31 लाख रुपए की लागत से निर्मित ‘ऑपरेशन सिंदूर उद्यान’ का लोकार्पण विगत अंश्रय माह में क्षेत्रीय विधायक श्री अजय चंद्राकर द्वारा किया गया था।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाइवलीहुड (भखारा-भतेली) केंद्र का उद्घाटन भी किया गया तथा युवाओं को प्रशिक्षण कित प्रदान की गई। इन पहलों के माध्यम से क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ युवाओं के कौशल विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसरों को भी

बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में उद्यान में पौधों की बढ़ती हरियाली और विकसित होता स्वरूप इस पहल के सकारात्मक परिणामों को दर्शा रहा है। आने वाले समय में पेड़-पौधों के और विकसित होने के साथ यह उद्यान भखारा क्षेत्र के लिए एक सुंदर हरित स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। पर्यावरण संरक्षण और कौशल विकास को एक ही परिसर में बढ़ावा देने वाली यह पहल विकास के साथ प्रकृति के संतुलन का सार्थक उदाहरण बन रही है।

पीएम सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना से पूरन को मिली बड़ी राहत

खैरागढ़। प्रधानमंत्री सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना जिले के लोगों के लिए बिजली खर्च में राहत के साथ स्वच्छ ऊर्जा अपनाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। इसी क्रम में विकासखंड छुईखदान के ग्राम टिकरीपारा निवासी श्री पूरन दास मानिकपुरी ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कर सौर ऊर्जा को अपनाया है। पूरन दास मानिकपुरी ने बताया कि सोलर प्लांट स्थापित करने से पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग 5 हजार रुपये आता था। प्रधानमंत्री सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के बाद अब उनका बिजली बिल 1 हजार रुपये



से भी कम रह गया है। इससे उन्हें हर महीने बिजली खर्च में बड़ी आर्थिक बचत हो रही है। सौर ऊर्जा के उपयोग से न केवल बिजली खर्च में कमी आई है, बल्कि श्री मानिकपुरी स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी योगदान दे रहे हैं। घर की छत पर स्थापित 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट उन्हें बिजली की जरूरत पूरी करने में मदद कर

रहा है और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भी कम हुई है। योजना से मिले लाभ से उत्साहित पूरन दास मानिकपुरी अब अपने आसपास के लोगों को भी प्रधानमंत्री सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे लोगों से अपने घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कर बिजली की बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से श्री पूरन दास मानिकपुरी की यह पहल आर्थिक बचत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर सामने आई है।

संक्षिप्त समाचार

सेवानिवृत्ति के दिन ही मिले सभी स्वत्व देयक और सम्मानजनक विदाई : राजवाड़े

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने विभागीय प्रशासन में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए सेवानिवृत्ति प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन की लंबी सेवा देने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कठिनाई का सामना न करें, यह विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने प्रमुख सचिव, संचालक समाज कल्याण तथा संचालक महिला एवं बाल विकास को निर्देशित किया है कि विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रकरणों की अग्रिम तैयारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति आदेश, पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य सभी देय स्वत्व देयकों का निराकरण सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाए, ताकि संबंधित कर्मचारी को उसके सेवानिवृत्ति दिवस पर ही सभी आदेश और भुगतान उपलब्ध हो सकें। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि प्रायः यह देखा गया है कि कई बार न मांग न जांच प्रमाण पत्र, सेवा सत्यापन तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया में विलंब होने से कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है। कुछ मामलों में प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रकरण देर से प्रस्तुत होने के कारण भुगतान और अन्य लाभ प्रभावित होते हैं। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी स्तरों पर समयबद्ध कार्यसंस्कृति अपनाने के निर्देश दिए।

श्री गुरु ज्वेलर्स की दीवार में संध लगाकर 20 किलो चांदी के जेवर और सोने ले उड़े चोर

रायपुर। रावतपुरा कॉलोनी में स्थित श्री गुरु ज्वेलर्स में चोरों ने दुकान की दीवार में संध लगाकर अंदर घुसे और करीब 20 किलो चांदी, सोने के जेवर समेत कैश लेकर भाग खड़े हुए। चोरी गए सामान की कीमत 20 लाख रूपए से ज्यादा बताई जा रही है। सूचना मिलते ही टिकरापारा पुलिस पटनास्थल पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सकें। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने रावतपुरा कॉलोनी स्थित श्री गुरु ज्वेलर्स में रविवार की देर रात पहले दुकान की दीवार तोड़ी और उसमें संध लगाकर गड्ढा बनाया। इसके बाद उसी रास्ते से दुकान के अंदर दाखिल हुए और दुकान में रखे चांदी के जेवर, सोने के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। दुकान संचालक को सुबह दुकान खोलने पर चोरी का पता चला। इसके बाद उन्होंने फौज मामले की जानकारी टिकरापारा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके और उन तक जल्द से जल्द पहुंच सकें।

डिलोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 11 अगस्त तक

रायपुर। संचालक संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा सत्र 2026–27 हेतु संचालित सभी 4 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (1.Diploma Engg. & Arch, 2.CDDM/ID, 3.MOM/HMCT, 4.Diploma Engg. (Laterl Entry) में अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि को 11अगस्त 2026 को शाम 06 बजे तक बढ़ाया गया है।आई आई टी के परिणाम घोषित हो चुके हैं, इसलिए दुबुद्ध उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने हेतु रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाई गई है। अतिरिक्त संचालक संचालनालय तकनीकी शिक्षा नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त जानकारी के अनुसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया में अभ्यर्थी की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि में ही परिवर्तन किया गया है। शेष कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया की सभी तिथियां एवं कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार यथावत रहेंगे।

जब दिल्ली के मंच पर जीवंत हुई छत्तीसगढ़ की पंडवानी परंपरा



राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक मंच इंडिया हैबिटेट सेंटर में अपनी पूरी जीवंतता के साथ प्रस्तुत हुई। महान पंडवानी कलाकार और पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय तीजन बाई की स्मृति को समर्पित विशेष प्रस्तुति के साथ आईएचसी लोक संगीत सम्मेलन 2026 का शुभारंभ हुआ। पंडवानी की इस प्रस्तुति ने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को दिल्ली के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक बार फिर प्रमुखता से सामने रखा। इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्ट्राइन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पंडवानी कलाकार प्रभा यादव ने पारंपरिक संगीतकारों के साथ प्रस्तुति दी। महाभारत की कथाओं पर आधारित पंडवानी में कथा, गायन, संवाद, लय और अभिनय का ऐसा संयोजन देखने को मिला, जिसने छत्तीसगढ़ की इस विशिष्ट लोक शैली की ताकत और व्यापकता को सामने रखा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश की कला और संस्कृति से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व भी उपस्थित रहे। वरिष्ठ पत्रकार एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सलाहकार आर. कृष्ण दास, धरसीवा विधायक एवं फिल्म कलाकार अनुज शर्मा, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव तथा सांस्कृतिक कार्यकर्ता ने कार्यक्रम में भाग लिया। इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रो. (डॉ.) के.जी. सुरेश और अनेखा कला केंद्र की सचिव अनेखा ब्रह्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहीं।

राजधानी/छत्तीसगढ़

राजधानी में निकली तिरंगा यात्रा मुख्यमंत्री साय ने भरी हुंकार

कहा- आसानी से नहीं मिली आजादी, वीरों ने दिया बलिदान

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने आज राजधानी रायपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। ‘मोर तिरंगा, मोर अभिमान–हर घर तिरंगा अभियान’ के तहत आयोजित इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत प्रदेश के कई मंत्री, विधायक के साथ बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए।

रायपुर के इंडोर स्टेडियम से भव्य तिरंगा यात्रा की कार्यक्रम का आगाज हुआ। देशभक्ति के रंग से सराबोर इस आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे, डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा,



मंत्री राजेश अग्रवाल, मंत्री ओपी चौधरी, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, विधायक राजेश मृण्त और विधायक सुनील मूनी समेत बीजेपी के अनेक नेता-कार्यकर्ता के साथ

स्काउट एंड गाइड्स, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली छात्र-छात्राएं समेत समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। इंडोर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे। इस दौरान मौजूद युवाओं और स्कूली बच्चों में खासा उत्साह देखने

को मिला। तिरंगा यात्रा इंडोर स्टेडियम से निकलकर गणेश मंदिर तिराहा, बूढ़ापारा बिजली ऑफिस, नगर निगम भवन, महिला थाना चौक और फायर ब्रिगेड चौक होते हुए सुभाष स्टेडियम पहुंची। आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तिरंगा देशवासियों को एक सूत्र में बांधकर रखता है। देश को आजादी आसानी से नहीं मिली, इसके लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस समेत देश के अनेक वीरों ने त्याग और बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत करते हुए लोगों से

अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के वीरों को नमन करते हुए कहा कि जवानों के अदम्य साहस से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हुआ है। अब उन क्षेत्रों में भी पहली बार तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जहां कभी नक्सलवाद का प्रभाव था। यह यात्रा सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि देश के वीर शहीदों के बलिदान को याद करने और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने का माध्यम है। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिल रही है।

तिरंगा यात्रा पर पूर्व सीएम बघेल ने कहा जो कहती है उसके विपरीत चलती है भाजपा : भूपेश

रायपुर। तिरंगा यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 52 साल तक आरएसएस कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, छत्तीसगढ़ में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बीजेपी जो कहती है उसके विपरीत चलती है। मोदी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, आज देश बिक रहा है, यह क्षय राष्ट्रवाद है। राम नाम जपना पराया माल अपना, अब तो राम का माल भी नहीं छोड़ रहे हैं।

प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व सीएम बघेल ने कहा, कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। एक सप्ताह में 6 ड्क 6 हत्याएं हो रही है। एक ही युवती से दो बार गैंगरेप हो रहा है। गृह मंत्री का ध्यान पंचायत की ओर है। अब गांवों में टेक्स लेने का फरमान जारी हुआ है। एक हजार रुपए क्या दिए उसके बदले वसूलना शुरू कर दिए हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल में अब फीस देना पड़ रहा है।



छत्तीसगढ़ में बाढ़ से निपटने की तैयारी तेज 18 को टेबल-टॉप और 20 को होगी मॉक ड्रिल

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक उच्चस्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन**
- एनडीएमए ने दी राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में गाइडलाइन्स**

रायपुर। राज्य में संभावित बाढ़ आपदा से निपटने और पूर्व तैयारियों को पुखा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक उच्चस्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि प्रदेश में अंतर-विभागीय समन्वय को परखने के लिए 18 अगस्त को राज्य स्तरीय टेबल-टॉप एक्सरसाइज और 20 अगस्त को व्यापक मॉक एक्सरसाइज (मॉक ड्रिल) का आयोजन किया जाएगा।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अधिकारियों को निर्देश दिे हैं कि वे टेबल-टॉप एक्सरसाइज की सभी प्रक्रियाओं और एसओपी को गहराई से समझें। उन्होंने कहा कि वास्तविक आपदा के समय शून्य देरी से राहत और बचाव कार्य संचालित करने के लिए यह पूर्वाभ्यास बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।

कॉन्फ्रेंस के दौरान बाढ़ के समय विभिन्न विभागों की सक्रिय भूमिका और समन्वय पर विस्तृत समीक्षा की गई। आपदा के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण, जल

संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट

हिमांशु मिश्र

सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव का असर संसद के मानसून सत्र के कामकाज पर साफ दिखाई दे रहा है। सत्र की अब तक हुई 15 बैठकों में दोनों सदनों की कार्यवाही कुल 88 बार स्थगित हो चुकी है। राज्यसभा 46 बार और लोकसभा 42 बार स्थगित हुई। सामान्य तौर पर दोनों सदनों में प्रतिदिन 7 से 8 घंटे कामकाज की उम्मीद रहती है, लेकिन इस सत्र में औसतन करीब एक-एक घंटे ही काम हो सका। इससे संसद के कामकाज और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कामकाज के आंकड़े बताते हैं कि लोकसभा में इन 15 बैठकों के दौरान एक बार भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। प्रश्नकाल में सांसद सरकार से सीधे सवाल पूछते हैं, जबकि शून्यकाल में जरूरी और तत्काल सार्वजनिक मुद्दे उठाए जाते हैं। दोनों सदनों में कुल 10 विधेयक प्रस्ताव हुए, लेकिन हंगामे के कारण विपक्ष की ओर से लाए गए स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो सकी। यानी सदन में कानून बनाने का काम तो हुआ, लेकिन कई मुद्दों पर विस्तार से बहस का अवसर नहीं मिल सका। इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसदीय कामकाज को लेकर आरोप-प्रत्यारोप और तेंज हो गए हैं। नीट पेपर लोक का मुद्दा इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का बड़ा कारण रहा। दोनों सदनों में इस मामले पर करीब 20 घंटे चर्चा हुई। हालांकि, आरोप है कि चर्चा के दौरान गिने-चुने सांसदों को छोड़कर ज्यादातर वक्त सियासी आरोप और प्रत्यारोप में चला गया। सरकार का कहना है कि विपक्ष चर्चा से बच रहा है और सदन में हंगामा करना उसका एजेंडा बन गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्ष बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विधेयकों पर सहमति देता है, लेकिन सदन में हंगामा करता है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद धर्मेन्द्र यादव ने सरकार को टकराव के लिए जिम्मेदार ठहराया और नीट पेपर लोक आंदोलन के दौरान हुई ज्यादतियों पर जवाब की मांग की। सरकार का आरोप है कि विपक्ष सदन में चर्चा के बजाय लगातार हंगामा कर रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार विपक्ष बीएसपी की बैठक में विधेयकों पर सहमति देता है और फिर सदन में हंगामा करता है। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि सरकार जरूरी मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेन्द्र यादव ने नीट पेपर लोक आंदोलन में हुई कथित ज्यादतियों पर जवाब मांगते हुए गृह मंत्री के सदन में बयान की मांग उठाई है। विपक्ष का सवाल है कि जब किसी मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है तो उसे सदन में रखने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। इस तरह दोनों पक्षों के बीच आरोपों का सिलसिला जारी है। 15 बैठकों में कामकाज की तस्वीर-
राज्यसभा की कार्यवाही 46 बार स्थगित हुई, लोकसभा 42 बार स्थगित हुई और दोनों सदनों को मिलाकर 88 बार कार्यवाही रोकी गई। दोनों सदनों में प्रतिदिन अपेक्षित 7-8 घंटे के मुकाबले करीब एक-एक घंटे काम हो सका। लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। 10 विधेयक पारित हुए, लेकिन विपक्ष के स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो सकी। नीट पेपर लोक पर करीब 20 घंटे चर्चा के बावजूद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप हावी रहे। ऐसे में मानसून सत्र का बड़ा हिस्सा सरकार और विपक्ष के टकराव में निकलता दिख रहा है। सवाल अब यही है कि क्या बाकी बैठकों में दोनों पक्ष गतिरोध तोड़कर महत्वपूर्ण विधेयकों और जनहित के मुद्दों पर सामान्य तरीके से चर्चा कर पाएंगे।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे....)

ठीक इसी तरह वर्तमान गवेषकों ने जो पृथ्वी का परिमाण 7967 माइल बतलाया है वह पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक होने वाली लम्बाई का परिमाण है जिसे व्यास कहते हैं। परन्तु पुराणग्रन्थों में पृथ्वी के पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुसार उसका घनफल (रकबा) निकल कर दिखलाया है जो पूरा पचास करोड़ योजन होता है।

सनातनधर्म के प्रसिद्ध वक्ता स्वामी दयानन्द जी ने अपने धर्म-कल्पद्रुम श्रादि ग्रन्थों में उक्त दोनों प्रकार के पृथ्वी परिमाणों का समन्वय इस प्रकार किया है पृथ्वी का व्यास 7667 माइल है। दो माइल का पुरातन क्रोश (कोस) और चार कोस का एक योजन- इस तरह सींधे शब्दों में पृथ्वी का व्यास पूरा एक हजार योजन हुआ।

यदि गोल अण्डाकार वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफालात्मक घनपरिमाण (रकबा) निकालना अभीष्ट हो तो उसके

व्यास को क्रमशः तीन बार गुणित (जरब) करके दो पर विभक्त (तकसीम) कर देना चाहिए, जो फल हो वही उसका पृष्ठ-क्षेत्र-फलात्मक घनपरिमाण होगा। तदनुसार 10000×10000× 10000/2 = 50,00,00,000 पचास करोड़ ही पृथ्वी का घनपरिमाण आयेगा। इसी रीति से हमारी इस मानव-पृथ्वी का परिमाण भी पुराण ग्रन्थों में जो कुछ लिखा है वही गणित द्वारा ठीक साबित होता है।

इसी प्रकार हिमालय आदि पर्वतों के परिमाणों की बात है। वर्तमान भूगोल-वेताओं ने हिमालय पर्वत की ऊँची चोटी, माउन्ट एवरेस्ट – जिसका वास्तविक नाम गौरीशिखर या गौरीशङ्कर है- की ऊंचाई केवल उन्तीस हजार फुट बताई है, परन्तु श्रीमद्भागवत के पञ्चमस स्कन्ध में इसका दश हजार योजन परिमाण लिखा है जो वर्तमान परिमाण से कहीं अधिक है। अब प्रश्न हो सकता है कि यह भेद क्यों ?

क्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

परीक्षा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनों के मायने

अजय बोकिल

जेन जी का पहले जंतर-मंतर पर नीट पेपर लोक के खिलाफ आंदोलन और अब झारखंड में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षा में भारी भ्रष्टाचार को लेकर चल रहा आंदोलन जहां देश में युवाओं के अपने अधिकारों को लेकर जागने का सुखद संकेत है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं का अब राजनीतिक दलों का नया दूल बनने का खतरा है, जिनका इस्तेमाल अपने सियासी हितों को साधने के लिए बड़ी चतुराई से किया जा रहा है।

दिल्ली के जेन जी आंदोलन के पीछे मुख्य भूमिका आम आदमी पार्टी, वामपंथियों और कुछ हद तक कांग्रेस की थी तो झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे आंदोलन के पीछे भाजपा है। दोनो आंदोलनों में युवाओं की मांगे जायज हैं, लेकिन उनसे डील करने का सरकारों का तरीका लगभग एक सा है। यानी पहले अनदेखा करो और पानी सिर से गुजरने लगे तो समझौता करो। दरअसल, छात्रों की समस्या का निदान करने से ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि कहीं विपक्ष इसका राजनीतिक लाभ न उठा ले। युवा भी सियासी दलों की धूर्तता को समझ रहे हैं। शायद इसी वजह से दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने खुद को गैर राजनीतिक संगठन बताते हुए युवाओं के हित में एक प्रेशर ग्रुप बनाने की बात कही है।

दिल्ली में जेन जी का आंदोलन तो केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉ.धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के साथ फिलहाल समाप्त हो गया है। लेकिन इस आंदोलन ने युवाओं को अपनी ताकत का अहसास करा दिया है। ऐसे में जिन राज्यों में जहां लगेगा कि युवाओं के अन्याय हो रहा है, अब आगे भी आंदोलन होते रहेंगे। क्योंकि युवाओं की समझ आ गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अलबत्ता जंतर-मंतर और झारखंड के युवाओं के आंदोलन में बुनियादी फर्क यह है कि दिल्ली में युवा बेदाग और पारदर्शी शिक्षा पद्धति के लिए लड़ रहे थे तो झारखंड के शिक्षित युवा योग्यतानुसार सरकारी नौकरियों में चयन की पारदर्शिता के लिए लड़ रहे हैं।

यू तो भ्रष्टाचार देश के अधिकांश लोक सेवा आयोगों में है, लेकिन झारखंड ने तो लगता है कि आंख का पर्दा भी खत्म कर दिया है। यहां आंदोलन में पदों के हिसाब से रेट लिस्ट तक टंग गई है। यह आंदोलन झारखंड लोक सेवा आयोग



(जेपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा में भारी धांधली के खिलाफ शुरू हुआ था। रांची के जयपालसिंह स्टेडियम में छात्र नेता देवेन्द्रनाथ महतो ने छात्रों की मांगों के समर्थन में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इसे जंतर मंतर पर अनशन करने वाले सोनम वांगचुक का भी समर्थन प्राप्त है।

दरअसल, समूचे विवाद की शुरुआत 2 जुलाई की रात से हुई, हुई, जब जेपीएससी ने परीक्षा में 103 सिविल सेवा पदों के लिए 2 हजार 204 अभ्यर्थियों के सफल होने की घोषणा की। लेकिन शुरुआती खुशी का माहौल जल्द ही विवाद में बदल गया। क्योंकि एक तो जेपीएससी ने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए केवल 17 दिन का समय दिया। और नतीजे जारी करते समय विभिन्न श्रेणियों के कट-ऑफ अंक जारी नहीं किए जबकि यह पारदर्शिता की बुनियादी शर्त है। इससे लगा कि दाल में काला है। कुछ ही हफ्तों में यह विवाद आपराधिक जांच तक पहुंच गया।

21 जुलाई को झारखंड सीआईडी ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता के अलावा परीक्षा प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्सों की जिम्मेदारी संभालने वाली लखनऊ की कंपनी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लि (टीडीपीएल) के निदेशक और कर्मचारी शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि टीडीपीएल को पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ब्लैकलिस्ट कर चुका था। फिर भी उसे जेपीएससी में भरती का ठेका मिला।

परीक्षा प्रक्रिया में डिजिटल छेड़छाड़ और ओएमआर शीट में गड़बड़ियों के खुलासे के बाद जेपीएससी के अध्यक्ष एवं रा्य के पूर्व मुख्य सचिव रहे एल. खिरांगते ने पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सहित नौ प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं। इससे लाखों परीक्षार्थियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उनके पास सड़क पर उतरने के

अलावा कोई चारा नहीं बचा। उन्हीं दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पेपर लोक के खिलाफ जेन जी का आंदोलन शबाब पर था।

झारखंड के आंदोलनरत छात्रों की मांग है कि जेपीएससी द्वारा आयोजित 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए, कथित अनियमितताओं की जांच सीआईडी के बजाए सीबीआई से कराई जाए, परीक्षा के श्रेणीवार कट-ऑफ अंक जारी किए जाएं, जेपीएससी और जेएसएससी दोनो की कार्यण्णाली में संरचनात्मक सुधार किए जाएं, भविष्य की भरतियों में अधिक पारदर्शिता लाई जाए और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता से समझौता करने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है। कांग्रेस सरकार में भी शामिल है। चूंकि यह आंदोलन विपक्ष द्वारा शासित राज्य की सरकार के खिलाफ चल रहा था, इसलिए भाजपा उसे खुलकर समर्थन दे रही है। जो ट्रेल आर्मी दिल्ली के जेन जी आंदोलन को एंटी नेशनल और बदचलन युवाओं का आंदोलन बता रही थी, वही झारखंड के छात्रों के आंदोलन को सार्व्विक और जायज बता रही है। इसके विपरीत सोशल मीडिया की जो फौज जंतर मंतर आंदोलन के देश के युवाओं की आवाज बता रही थी, वो झारखंड के युवाओं के आंदोलन को प्रायोजित और फर्जी बताने में संकोच नहीं कर रही है।

इस पूरे मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भूमिका टालमटोल की ज्यादा है। वो आंदोलन के प्रति संवेदनशीलता तो दिखा रहे हैं, लेकिन युवाओं की मांगों का निदान करने में हीलाहवाली कर रहे हैं। इसके पीछे डर छिपा है कि अगर आंदोलन सफल हो गया तो भाजपा इसका सेहरा अपने सिर बांधने से नहीं चूकेगी। दिलचस्प यह है कि भाजपा और उसके सहयोगी संगठन छात्रों की मांगों न मानने के लिए सीधे मुख्यमंत्री को घेरने के बजाए कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। क्योंकि उसे अगले चुनाव में झामुमो से समझौते की आस है।

उत्तर जंतर मंतर के आंदोलनकारी छात्रों के लिए लगातार सहानुभूति जता रही कांग्रेस के झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने निर्लज्जता से कहा कि परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है। यह सब भाजपा का खेला है। इस बयान के बाद जब कांग्रेस की ट्रेलिंग

होने लगी तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस आंदोलन के प्रति भी सहानुभूति जतानी पड़ी। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि वो आंदोलनकारी छात्रों की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कराएंगे। हालांकि ये बात कब और कैसे होगी, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। जबकि भाजपा लगातार सवाल कर रही है कि जेन जी के प्रति जैसी सहादती राहुल और कांग्रेस ने दिखाई वैसी झारखंड के छात्रों को लेकर क्यों नहीं है? इसी बीच सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी आंदोलन को समर्थन दे दिया है और कहा है कि वो जहां भी जरूरत होगी, युवाओं के हकों के लिए लड़ेंगे।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो युवा अब किसी भी सत्तारूढ़ दल की चूल्हें हिलाने का प्रभावी दूल बनते जा रहे हैं। क्योंकि समस्याएं हर राज्य में हैं। इसके लिए सत्ताधारी दल पर निशाना साधने के लिए युवाओं के कंधों की ताकत का अहसास राजनीतिक पार्टियों को हो गया है। अभिजीत दिपके के अधोषिप्त मार्गदर्शक अरविंद केजरीवाल जेन जी के हक में तो खूब बोले, लेकिन आप शासित पंजाब में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोपों पर मौन हैं। करीब दस राज्यों में ऐसी ही परीक्षाओं और भर्ती में गड़बड़ियों के गंभीर आरोप हैं। लेकिन सरकारों का रवैया सिलेक्टिव है।

यहां असल मुद्दा राजनीतिक रूप से अपनी कमीज के मुकाबिल दूसरे की कमीज ज्यादा गंदी दिखाने से ज्यादा व्यवस्था और भ्रष्टाचार के गड़ों को भरकर पूरे परीक्षा तंत्र को एक विश्वसनीय बनाने की जरूरत है। जिसे कालीन के नीचे सरकाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर गहरी चिंता तो है कि आज जेन जी और जेन अल्फा के युवा कल के चालीस करोड़ से ज्यादा मतदाता होंगे और उनका असंतोष किसी को भी सत्ता से बेदखल करने के लिए काफी होगा। लिहाजा उन्हें कैसे साधें ताकि सत्ता को डोर भी हाथ में रहे। हालांकि इसके लिए युवा सड़कों पर ही उतरें, यह जरूरी नहीं है। तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह सत्ता परिवर्तन ईवीएम से ही हो गया। जेन जी का भारत की भावी राजनीति और निर्माण में कितना महत्व है यह सरसंघचालक द्वारा मुंबई में जेन जी से संवाद और उनके आंदोलनों को जायज ठहराने से समझा जा सकता है। बावजूद इसके ट्रेल आर्मियां अभी भी निंदा अभियान में उसी शिद्दत से जुटी हैं।

भारत के सबसे युवा बलिदानी थे खुदीराम बोस

मृत्युंजय दीक्षित

देश की आजादी की लड़ाई में कुछ नौजवानों का बलिदान इतना उद्देलित करने वाला था कि उसने पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम का रूख बदलकर रद दिया। इनमें एक नाम खुदीराम बोस का है, जिन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र महज 18 साल कुछ महीने थी। अंग्रेज सरकार उनकी निडरता और वीरता से इस कदर आतंकित थी कि उनकी कम उम्र के बावजूद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गयी।

खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसम्बर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के एक गांव में बाबू त्रैलोक्य नाथ के घर पर हुआ था और माता का नाम लक्ष्मीप्रिया देवी था। बोस ने नौवीं कक्षा के बाद से ही पढ़ाई छोड़ दी थी।

1900 के दशक के आरम्भ

में अरबिंदो घोष और बहन निवेदिता के सार्वजनिक भाषणों ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वे स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय स्वयंसेवक बन गये। खुदीराम केवल 15 वर्ष के थे जब उन्हें ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ पर्चे बांटने के आरोप में पहली बार गिरफ्तार किया गया। 1908 में खुदीराम अनुशीलन समिति से जुड़ गये जो 20वीं सदी के आरम्भ में गठित एक क्रांतिकारी समूह था। अरबिंदो घोष और उनके भाई बोरेंद्र घोष जैसे राष्ट्रवादियों ने इस समिति का नेतृत्व किया। अनुशीलन समिति का सदस्य बनने ही खुदीराम पूरी तरह से क्रांतिकारी बन गये और उन्होंने यहीं से बम आदि बनाने और चलाने का



हो गये थे। उन्होंने बंगाल विभाजन का भी विरोध किया और युगांतर के सदस्य बनकर आंदोलन में हिस्सा लिया। उन दिनों अनेक अंग्रेज अधिकारी भारतीयों से दुर्व्यवहार करते थे। ऐसा ही एक मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर बिहार में तैनात था। वह छोटी -छोटी बातों पर भारतीयों को दंड देता था। अतः क्रांतिकारियों ने उससे बदला लेने का निश्चय किया।

कोलकाता में प्रमुख क्रांतिकारियों की बैठक हुई। बैठक में किंग्सफोर्ड को यमलोक पहुंचाने की योजना पर गहन

प्रशिक्षण प्राप्त किया।

उस समय अंग्रेजों की ओर से भारतीयों पर घोर अत्याचार किये जा रहे थे जिससे आम भारतीयों में गहरा आक्रोष था। स्कूल छोड़ने के बाद बोस

रिवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गये थे। उन्होंने बंगाल विभाजन का भी विरोध किया और युगांतर के सदस्य बनकर आंदोलन में हिस्सा लिया। उन दिनों अनेक अंग्रेज अधिकारी भारतीयों से दुर्व्यवहार करते थे। ऐसा ही एक मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर बिहार में तैनात था। वह छोटी -छोटी बातों पर भारतीयों को दंड देता था। अतः क्रांतिकारियों ने उससे बदला लेने का निश्चय किया।

कोलकाता में प्रमुख क्रांतिकारियों की बैठक हुई। बैठक में किंग्सफोर्ड को यमलोक पहुंचाने की योजना पर गहन

विचार विमर्श हुआ। बोस ने स्वयं को इस कार्य के लिए उपस्थित किया वह भी तब जब उनकी अवस्था बहुत कम थी। उनके साथ प्रफुल्ल कुमार चाकी को भी इस अभियान को पूरा करने का दायित्व सौंपा गया। दोनों युवकों को एक बम, तीन पिस्तौल व 40 कारतूस दिये गये। दोनों ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर एक धर्मशाला में डेरा जमा लिया। कुछ दिन तक किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का अध्ययन किया। इससे उन्हें पता लग गया कि वह किस समय न्यायालय आता-जाता है पर उस समय उसके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहता था। अतः उस समय उसे मारना कठिन था। अतः उन्होनें उसकी दिनचर्या पर ध्यान दिया। किंग्सफोर्ड प्रतिदिन शाम को लाल रंग की बग्घी में क्लब जाता था। दोनों ने किंग्सफोर्ड को उसकी समाप्त करने का निर्णय लिया।

ढाका की राजनीति और भारत-बांग्लादेश संबंधों की नई परीक्षा

ललित गर्ग



वातावरण से दिया जाए, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होती है। शेख हसीना की वापसी को केवल एक व्यक्ति की वापसी के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की परीक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि अवामी लीग को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखने की कोशिश होती है, तो यह बांग्लादेश के लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाएगा। वास्तविकता यह भी है कि बांग्लादेश की राजनीति आज केवल अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनललिस्ट पार्टी (बीएनपी) के बीच सत्ता संघर्ष तक सीमित नहीं रह गई है। अब यह संघर्ष राष्ट्र की ऐतिहासिक पहचान, 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत और भविष्य की वैचारिक दिशा का भी बन चुका है। अवामी लीग स्वयं को मुक्ति संग्राम की मूल चेतना का प्रतिनिधि बताती है, जबकि बीएनपी भी अब उसी विरासत पर अपना दावा प्रस्तुत कर रही है। इतिहास की इस प्रतिस्पर्धी व्याख्या ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और गहरा किया है। ऐसी परिस्थितियों में शेख हसीना की वापसी केवल राजनीतिक समीकरण नहीं बदलेगी, बल्कि राष्ट्रीय विमर्श की दिशा भी प्रभावित करेगी। सरकार

इन परिस्थितियों में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और बांग्लादेश के संबंध केवल दो पड़ोसी देशों के रिस्ते नहीं हैं, बल्कि साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा, आर्थिक सहयोग और सामरिक हितों पर आधारित हैं। पिछले डेढ़ दशक में दोनों देशों के संबंधों में अभूतपूर्व निकटता आई,

जिसका एक बड़ा आधार शेख हसीना सरकार और नई दिल्ली के बीच बना विश्वास था। सीमा विवादों का समाधान, ऊर्जा सहयोग, संपर्क परियोजनाएं, आतंकवाद के विरुद्ध साझा कार्रवाई तथा पूर्वीतर भारत की कनेक्टिविटी जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन ने इस विश्वास की नई परीक्षा शुरू कर दी है। नई दिल्ली ने एक ओर शेख हसीना को सुरक्षा और आश्रय दिया है, वहीं दूसरी ओर उसने ढाका की नई सरकार से संवाद भी जारी रखा है। यही परिपक्व कूटनीति का परिचायक है। भारत के सामने चुनौती किसी एक राजनीतिक दल के साथ खड़ा दिखाई देने की नहीं, बल्कि पूरे बांग्लादेश के साथ स्थायी और संतुलित संबंध बनाए रखने की है। इस संदर्भ में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला बारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है। यदि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इसमें भाग लेते हैं और भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ सकारात्मक संवाद होता है, तो दोनों देशों के बीच हाल के तनावों को कम करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह केवल औपचारिक शिखर बैठक नहीं होगी, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का अवसर भी होगी। भारत को इस मंच का उपयोग केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सुरक्षा सहयोग पर भी स्पष्ट संवाद स्थापित करना चाहिए।

भारत के सामने अनेक जटिल प्रश्न भी हैं। गंगा जल संधि के नवीनीकरण, तीस्ता जल बंटवारे, सीमा-पार व्यापार, अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा तथा शेख हसीना के प्रत्यर्पण जैसे मुद्दे आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करेंगे। इनमें किसी भी विषय पर भावनात्मक या राजनीतिक प्रतिक्रिया के बजाय कानूनी, कूटनीतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा। विशेष रूप से प्रत्यर्पण का प्रश्न केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून और राजनीतिक परिस्थितियों से

भी जुड़ा हुआ है। भारत को अपनी संधियों, न्यायिक प्रक्रियाओं और रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। दूसरी ओर बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव भी नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय है। वर्तमान सरकार के शुरुआती महीनों में चीन के साथ बढ़ते संपर्क और सामरिक महत्व की परियोजनाओं पर समझौते इस बात का संकेत हैं कि ढाका अपनी विदेश नीति में संतुलन साधने का प्रयास कर रहा है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिस्पर्धा की मानसिकता के बजाय विश्वास और विकास की साझेदारी को प्राथमिकता दे। यदि भारत आर्थिक सहयोग, निवेश, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी साझेदारी के नए अवसर प्रस्तुत करता है, तो दोनों देशों के संबंध और अधिक मजबूत हो सकते हैं।

शेख हसीना की वापसी का प्रश्न अंततः बांग्लादेश के लोकतांत्रिक चरित्र की परीक्षा है। यदि उन्हें निष्पक्ष राजनीतिक अवसर मिलता है, तो जनता स्वयं तय करेगी कि भविष्य का नेतृत्व किसे सौंपना है। लेकिन यदि राजनीतिक प्रतिशोध, दमन और हिंसा का वातावरण बना रहता है, तो इससे न केवल बांग्लादेश की लोकतांत्रिक साख प्रभावित होगी, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत को इस पूरे घटनाक्रम में संयम, संतुलन और दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ना होगा। न तो उसे किसी आंतरिक राजनीतिक विवाद का पक्षकार बनना चाहिए और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा करनी चाहिए। भारत की विदेश नीति का मूल उद्देश्य एक स्थिर, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध पड़ोस होना चाहिए। यही उसकी सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए सबसे अनुकूल स्थिति होगी। आज आवश्यकता किसी राजनीतिक विजय की नहीं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता की है। बांग्लादेश को यह सिद्ध करना होगा कि लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं, बल्कि विपक्ष के सम्मान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अधिभ्यक्त की आजादी और राजनीतिक सहिष्णुता का भी नाम है।

आज का इतिहास

1347 अलाउद्दीन हसन गंगू ने राजसी सत्ता हासिल की और बहमनी वंश की स्थापना की।

1863 कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित देश बना।

1914 फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और हंगरी पर आक्रमण की घोषणा की।

1914 पॉलैंड से यहूदियों को निकाला गया।

1929 पर्शिया और इराक के बीच मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए।

1940 ब्रिटेन के पोर्टलैंड बंदरगाह पर जर्मनी ने हवाई हमला किया।

1908 क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई।

1914 फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।

1929 पर्शिया और इराक के बीच मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए।

1940 ब्रिटेन के पोर्टलैंड बंदरगाह पर जर्मनी ने हवाई हमला किया।

1944 अमेरिका ने सुमात्रा द्वीप समूह के पालेमबेंग क्षेत्र पर हवाई हमला किया।

1960 अफ्रीकी देश चाड ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की।

1961 दादर नगर हवेली का भारत में विलय और इसे केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया।

1984 लॉस एंजलीस ओलंपिक खेलों में दक्षिण अफ्रीकी मूल की ब्रिटिश धावक जोला बड 3000 मीटर की दौड़ में अमेरिका की शीर्ष धावक मैरी डेकर से टकरा गई। मैरी को दौड़ से बाहर होना पड़ा। यह घटना दुनियाभर में खूब चर्चित रही।

1984 तत्कालीन सोवियत रूस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।

1999 सदी का अंतिम चंद्रग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में करोड़ों लोगों ने देखा। कुछ हिस्सों में घने बादलों की वजह से लोग इसे नहीं देख सके।

2000 फिजी के विद्रोही नेता जार्ज स्पेट के ख़लिाफ़ देशद्रोह का मुकदमा चलाने का निर्णय।

2001 उत्तरी आयरलैंड विधानसभा भंग, आयरिश विद्रोहियों को निशस्त्रीकरण के लिए दो सप्ताह का समय।

2003 उत्तर अफ़्रीक़ाईक संवि संगठन नाटो ने अफगानिस्तान में शांति बल की कमान संभाली।

2004 भारत और पाकिस्तान ने वांछित अपराधियों की सूचियों की अदला-बदली की।

2006 पाकिस्तान ने तीसरी अगोस्टा 90बी श्रेणी की पुनडुब्बी का जालावरण किया।

2007 मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने।

2008 एकीकृत इस्पात मैनुफ़ैक्चरर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात ने छत्रीसगढ़ सरकार के साथ 1570 करोड़ रुपये के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये।
आज के नायक पार्श्वनाथ रितेल में स्वतन्त्र निदेशक नियुक्त हुए।

प्रशांत की जीत: बिहार में एक नए विपक्ष का संकेत और बदलती राजनीति

वृजेश मिश्रा

बिहार की राजनीति पिछले तीन दशकों से मुख्यतः दो व्यक्तित्वों के आसपास घूमती रही है पहला लालू प्रसाद यादव और दूसरा नीतीश कुमार। इन दोनों नेताओं ने न केवल सत्ता पर लंबे समय तक प्रभाव बनाए रखा, बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा और विमर्श भी तय किए। एक ओर लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की राजनीति के नाम पर सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे हो वो बात दूसरी है कि उन्होंने सामाजिक न्याय के नाम जातिय विद्वेष को हवा दी उनके दौर में भूरा बाल साफ करो के नारे खूब सुनाई पड़े और सामाजिक न्याय के नाम केवल स्वयं का और अपने परिवार का विकास करते हुए दिखाई पड़े, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार ने सुशासन, सड़क, बिजली, शिक्षा औ आधारभूत विकास को अपनी पहचान बनाया।

बहरहाल, समय के साथ दोनों नेताओं की राजनीतिक स्वीकार्यता और सीमाएं भी सामने आईं। अब जब लालू यादव राजनीतिक जीवन खत्म लगभग खत्म हो चुका है और नीतीश कुमार भी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तब बिहार की राजनीति एक नए नेतृत्व की खोज करती हुई प्रतीत हो रही है।

ऐसे समय में प्रशांत किशोर का उभरना केवल एक नए राजनीतिक दल का गठन नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प की संभावनाओं का संकेत भी माना जा सकता है। हालिया बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी की जीत ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है कि क्या बिहार की जनता अब पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर किसी नए नेतृत्व को अवसर देने के लिए तैयार हो रही है।

जनता दल (यूनाइटेड) की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि नीतीश कुमार के बाद ऐसा कोई सर्वमान्य नेता दिखाई नहीं देता, जो पूरे बिहार में उनकी तरह जन स्वीकार्यता रखता हो। यही स्थिति राष्ट्रीय जनता दल के सामने भी है। तेजस्वी यादव निश्चित रूप लालू यादव के बेटे होने के कारण बिहार में एक बड़े नेता के रूप में पहचान रखते हैं लेकिन अभी भी समाज के एक बड़े वर्ग में यह धारणा मौजूद है कि वे अपने पिता की राजनीतिक विरासत की छाया से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये काफी हद तक ठीक भी है कि तेजस्वी यादव के पास अपने पिता की बनाई गई पार्टी और मुस्लिम यादव गठजोड़ के अलावा कोई विशेष राजनीतिक समझ नहीं दिखाई पड़ती है।

इसी राजनीतिक रिक्तता के बीच प्रशांत किशोर का नाम तेजी से उभर रहा है। लंबे



समय तक देश के विभिन्न राज्यों में चुनावी रणनीतिकार के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने स्वयं सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। बिहार में उनकी पदयात्रा, गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद और शिक्षा, रोजगार, पलायन तथा प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों पर लगातार अभियान चलाने से उन्हें एक गंभीर राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान मिली।

प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी छवि पारंपरिक जातीय राजनीति से अलग दिखाई देती है। वे स्वयं को विकास, शिक्षा, रोजगार और सुशासन की राजनीति का पक्षधर बताते हैं। यही कारण है कि शिक्षित युवाओं, शहरी मध्यम वर्ग और

ऐसे मतदाताओं में उनकी चर्चा बढ़ी है जो बिहार में नई राजनीति की अपेक्षा रखते हैं।

हाल ही में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली सफलता को केवल एक सीट की जीत के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह जीत इस बात का संकेत भी है कि यदि कोई नया दल संगठित ढंग से चुनाव लड़े, स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता दे और विश्वसनीय उम्मीदवार प्रस्तुत करें, तो बिहार की राजनीति में उसके लिए स्थान बन सकता है। यद्यपि केवल एक चुनाव के आधार पर व्यापक निष्कर्ष निकालना अतिशयोक्त होगा, फिर भी इस परिणाम ने यह अवश्य दिखाया है कि प्रशांत किशोर की राजनीति को अब बिहारी की जनता का काफी बड़ा वर्ग गंभीरता से ले रहा है। यदि भविष्य में जनता दल (यूनाइटेड) का प्रभाव कम होता है और राष्ट्रीय जनता दल अपनी स्वीकार्यता का दायरा पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा पाती, तो विपक्ष के लिए एक नया राजनीतिक स्थान बन सकता है। इस स्थिति में प्रशांत किशोर उस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज बिहार में सबसे संगठित राजनीतिक दलों में से एक है। उसके पास मजबूत संगठन, संसाधन और कार्यकर्ताओं का व्यापक नेटवर्क है। ऐसे में भाजपा को चुनौती देना किसी भी विपक्षी दल के लिए आसान नहीं होगा। इसके

जेन-जी को जेन-जी ही रहने दें

सुधीश पत्तौरी

जेन-जी पीढ़ी बड़े भागों वाली है। कोई उसे पटा रहा है। कोई फुसला रहा है। कोई उकसा रहा है कि ‘जेन-जी’ तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जेन-जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।’ कोई कह रहा है कि ‘अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों!’ कोई उसे अपना चेला बनाने के चक्कर में है, तो कोई उसे ‘भगवान’ की तरह पधारने के चक्कर में है। कोई कह रहा है कि जेन-जी ने चमत्कार कर दिया। उसने अस्पष्ट को संभव कर दिखाया। जिसे कोई न कर पाया, उसने कर दिखाया। ऐसी जेन-जी पीढ़ी की जय हो! जय हो! एक बेहद घमंडी सरकार को उसने बात की बात में हिला दिया। जो किसी की नहीं मानती थी, उससे अपनी सारी मांगें मनवा लीं। बड़े-बड़े मंत्री कुछ ‘जेन-जी’ के आगे पीछे चक्कर मारते दिखे। उनके एक से एक नाज-नखरे उठाते दिखे।

जिस शिक्षा मंत्री को कोई नहीं हटा पाया, जेन-जी ने उसे हटवा दिया। छात्रों पर सारे केस वापस करवा दिए। ‘नीट पेपर लीक’ से पैदा हुई हताशा के कारण ‘आत्महत्या’ करने वाले छात्रों को कंपसेशन दिलाने की गारंटी ले ली। किसी से भी बात न करने वाले पीएम तक को सोशल मीडिया के जरिये जेन-जी से बात करने को मजबूर होना पड़ा। एक दिन भारत के ‘चीफ जस्टिस’ द्वारा ‘चलते-चलते’ किए कटाक्ष की प्रतिक्रिया में अमरीका में बैठे कुछ भारतीय ‘जेन-जी जनों’ ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ बना डाली। यही जेन-जी भारत सरकार को गले की हड्डी बन गए। ‘चौबीस बाई सात’ के मीडिया कवरेज ने ‘जेन-जी पीढ़ी’ को ‘जंतर मंतर’ में ‘विरोध का देवता’ बना दिया। अंततः सरकार झुकी और प्रधानमंत्री को कई ‘रीलों’ के जरिये जेन-जी पीढ़ी से संवाद करने की जरूरत हुई। नतीजतन जेन-जी पीढ़ी को ‘अपरिभाष्य मिथक’ में बदल दिया गया। फिर ‘संघ’ के मुखिया मोहन भागवत ने जेन-जी से बातचीत करके, जेन-जी के ‘भाव’ को और बढ़ा दिया कि जेन-जी ज्यादा ईमानदार है...कि जेन-जी

के सवालों का जबाव देना होगा...कि जेन-जी की शिकायतें सही हैं...कि जेन-जी से पहले बात करनी चाहिए थी...कि आंदोलन की संवाद का तरीका है...कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में कमी है...कि शिक्षा का बजट ‘छह प्रतिशत’ होना चाहिए...कि जेन-जी राष्ट विरोधी नहीं...कि संवाद की जरूरत है, मतभेद की नहीं...आदि। यह एक प्रकार की ‘मनोवैज्ञानिक ‘नजलिंग’ थी। ‘नजलिंग’ यानी टहोका या हल्का धक्का मारकर किसी रूठे को मानने, उसे ‘पुचकार’(पैंपर) कर, उसको ‘अलेले मेला मुन्ना मुन्नी’ आदि कह, उसकी ‘लल्ले-चप्पो’ कर उसे चुप करने की कोशिश। इस जेन-जी पीढ़ी को भूख हड़ताल और धरने पर बैठने के कारण मिली हमदर्दी ने हीरो बना दिया। बहुत से युवाओं के ‘आउट ऑफ कंट्रोल’ हो जाने पर भी पुलिस तो टागोरेत बनी, लेकिन उनके प्रति हमदर्दी कम न हुई और सरकार उनके आगे ‘लंबलेट’ नजर आई। अब भी उनकी जरा-सी धमकी भी राज्य की सारी मशीनरी को हकबका देती है। भाजपा के जिस अश्वमेध के घोड़े को बारह साल से कोई नहीं रोक पाया, उसे कुछ जेन-जी युवाओं ने अपने पिछवाड़े बांध लिया। इसे देख विपक्ष भी अपने फॉर्म में आ गया। इसीलिए लगभग सभी दल, नेता व बुद्धिजीवी, जेन-जी की लल्ले चप्पो करते, उसे मारते से, उसकी हां में हां मिलाते नजर आते हैं। कुछ विपक्षी जेन-जी को ‘दुलारने’(पेंपरिंग) में लगे दिखते हैं, कुछ ‘जेन-जी’ का ‘बिजुका’ दिखाकर सत्ता को डराते दिखते हैं कि अगर अब भी तुम्हारा अहंकार कम न हुआ व तुम न संभले और सड़ी-गली शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारा, बेरोजगारों को रोजगार न दिया, तो जेन-जी आ जाएगी और तुमको खो जाएगी। इसे देख कुछ ने ‘कॉकरोच पार्टी’ के कुछ नेताओं को ‘आप पार्टी’ का पूर्व सदस्य बताकर उन्हें एक्सपोज करने की भी कोशिश की। कुछ ने उन्हें ‘भारत विरोधी’ अरबपति ‘जाजें सोरोस’ से जुड़ा बताया, लेकिन जेन-जी का जलवा और धमक कम नहीं हुई।

एफसीआरए बिल: मार्को रुबियो का बयान सुनना चाहिए

नीरज कुमार दुवे

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक को लेकर देश में तो इस समय व्यापक बहस छिड़ी ही हुई है, साथ ही इसकी गूँज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो पहले स्वयं यह कह चुके हैं कि किसी भी देश में विदेशी फंड से संचालित संस्थाओं को वहां की संप्रभु सरकार के समानांतर व्यवस्था नहीं चलानी चाहिए और उन्हें मेजबान देश के कानूनों का सम्मान करना चाहिए। इसके बावजूद अमेरिकी सांसद राइली मूर भारत के प्रस्तावित कानून की आलोचना कर रहे हैं। दूसरी ओर, मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने उन्हें आश्चस्त किया है कि प्रस्तावित संशोधन को पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव) से लागू नहीं किया जाएगा। इन घटनाक्रमों के बीच मोदी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और भारतीय कानूनों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा।

हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में एफसीआरए के तहत पंजीकृत सक्रिय संगठनों की संख्या घटी है, लेकिन विदेशी चंदे का प्रवाह बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में 16,200 संगठनों को लगभग 22,963 करोड़ रुपये का विदेशी योगदान प्राप्त हुआ। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस निरस्त या समाप्त भी किए गए हैं। सरकार का कहना है कि केवल वैध पंजीकरण रखने वाले संगठनों को ही विदेशी धन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए।

हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा लाए गए संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त हो जाता है, रह हो जाता है, नवीनीकृत नहीं होता या संस्था स्वयं उसे छोड़ देती है, तो विदेशी धन से निर्मित परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक नामित प्राधिकरण की व्यवस्था की जाएगी। यदि बाद में संस्था का पंजीकरण बहाल हो जाता है तो संबंधित संपत्तियां और अग्रयुक्त विदेशी



योगदान वापस कर दिए जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता, तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार का तर्क है कि यह व्यवस्था किसी नए अधिकार का सृजन नहीं, बल्कि पहले से मौजूद प्रावधानों का अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने का प्रयास है।

वहीं प्रस्तावित संशोधन को लेकर कुछ चर्च संगठनों ने आशंकाएं भी व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि कानून की कुछ धाराएं अत्यधिक कठोर हैं और उन्हें संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से विभिन्न चर्च संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने अमित शाह के साथ बैठक के बाद कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित संशोधन को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा।

हम आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने इन आशंकाओं का विस्तार से जवाब भी दिया है। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून किसी विशेष धर्म, समुदाय या विचारधारा की निशाना नहीं बनाता। एफसीआरए के प्रावधान सभी विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले संगठनों पर समान रूप से लागू होते हैं। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी धार्मिक स्थल से जुड़ी संपत्ति का मामला आता है तो उसके धार्मिक स्वरूप को कानूनन सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही, नामित प्राधिकरण के आदेश अंतिम नहीं होंगे और उनके विरुद्ध न्यायालय में अपील का अधिकार भी

सनत जैन

देश की राजनीति में पिछले कुछ सप्ताह के घटनाक्रम ने यह संकेत दिया है। राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल विपक्ष नहीं, बल्कि देश का युवा वर्ग भी बनता जा रहा है। जेन-जी और जेन-अल्फा ऐसे दौर में खड़े हैं, जहां उनकी प्राथमिकताएं धर्म, जाति और भावनात्मक मुद्दों से अधिक शिक्षा, रोजगार, प्रणाली की पारदर्शिता और भविष्य की चिंता हैं। यही कारण है, छात्र आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। छात्र आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सच प्रमुख मोहन भागवत का स्वयं सामने आना राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, यदि समय रहते युवा वर्ग की नाराजगी धूर नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में भारी नुकसान हो सकता है। भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत, धार्मिक ध्ववीकरण थी, वह अपना प्रभाव खो सकती है। हर घर में पढ़ने वाला छात्र है, हर परिवार में रोजगार की चिंता है। प्रत्येक परिवार को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। यही चिंता अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा युवाओं को कॉकरोच कहे जाने की कथित टिप्पणी के बाद जो विवाद खड़ा हुआ है, उसने छात्र असंतोष को अधिक उग्र बना दिया है। अभिजीत दीपके द्वारा गठित कॉकरोच जनता पार्टी और उसके आंदोलनों ने राजनीतिक परिस्थितियों को नई दिशा दे दी है। माना जा रहा है, प्रारंभ में इस आंदोलन को नियंत्रित दायरे में रखने की



जो रणनीति भाजपा ने बनाई थी, वह पूरी तरह से विफल हो गई है। घटनाक्रम पूरी तरह से जो सोचा गया था, वह इलटा पड़ गया है। पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, भ्रष्टाचार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन 20 जुलाई के संसद चलो अभियान के बाद राष्ट्रीय मुद्रा बन गया। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, पेलट गन और पुलिस की कथित बर्बरतापूर्ण कार्रवाई ने आंदोलन को पेपर लीक मुद्दे और शिक्षा के मुद्दे तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे केंद्र सरकार के खिलाफ व्यापक असंतोष में बदल दिया है। देशभर में लगभग 200 स्थानों पर हुए प्रदर्शनों ने यह स्पष्ट कर दिया है। युवा अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं हैं। संगठित होकर वह अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पर आने की क्षमता भी रखता है। इस दौरान भाजपा और संघ से जुड़े कई नेताओं के बयानों ने आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया है। आंदोलन की आग को और भड़का दिया है। आंदोलनकारियों को राष्ट्रविरोधी, गैर-जिम्मेदार अथवा अन्य आपत्तिजनक विशेषणों से सत्ता पक्ष के द्वारा संबोधित

करने के प्रयासों ने युवाओं की नाराजगी कम करने के बजाय उसे और बढ़ा दिया है। यही वह मोड़ था, जहां संघ की चिंता हुई और उसे अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता महसूस हुई।

मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत का संविधान, बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर, आरक्षण तथा युवाओं के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक प्रश्नों पर खुलकर बोलना, केवल वैचारिक वक्तव्य नहीं है। संघ और उसके अनुवांशिक संगठनों की एक मजबूरी भी बन गई है। मोहन भागवत का यह कार्यक्रम एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। उन्होंने युवाओं की जिज्ञासाओं और प्रश्नों को लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा बताया। यह बदलाव इस बात का संकेत है, संघ और भाजपा अब टकराव की बजाय संवाद की रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें संघ कितना सफल होगा कहना मुश्किल है। संघ के संगठन में गोपनीयता और विचारों की अभिव्यक्ति की सीमित छूट होती है। वर्तमान युवा असीमित ज्ञान और असीमित इच्छाओं के साथ सड़कों पर उतरा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है, राहुल गांधी लगातार पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों को उठाकर युवा वर्ग में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं का यह वर्ग धार्मिक ध्ववीकरण से हटकर रोजगार, शिक्षा और आर्थिक अवसरों को लेकर

राहुल गांधी से प्रभावित हो रहा है। इसका असर आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान का आधार बनाता है, तो भारतीय राजनीति का पूरा विमर्श ही बदल सकता है। इस समय संघ और भाजपा दोहरे संकट से गुजर रही है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरी का मामला भी सुर्खियों में है। जिसने धार्मिक ध्ववीकरण को प्रभावित किया है। युवा सपनों के भरोसे नहीं, परिणामों के आधार पर निर्णय लेते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा आज उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। केवल बड़े वादों, भावनात्मक नारों और वैचारिक आधार पर अब युवा वर्ग मानने वाला नहीं। सरकारों और संवैधानिक संस्थाओं को पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, रोजगार सृजन, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, महंगाई और भ्रष्टाचार इत्यादि में ठोस पारदर्शी सक्षम परिणाम देने होंगे। इतिहास गवाह है, जब युवा संगठित होकर अपने भविष्य के प्रश्नों के साथ खड़ा होता है, तो राजनीति की दिशा बदल जाती है। जेन-जी और जेन-अल्फा को केवल चुनावी गणित से नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की निर्णायक शक्ति के रूप में देखना होगा। आने वाले समय में यह तय होगा, सत्ता उनकी आकांक्षाओं को वास्तविक नीतियों में बदलती है, या सपना ही दिखाती है। युवाओं का वर्तमान असंतोष भारतीय राजनीति का नया इतिहास बनता जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समय रहते युवाओं की बीमारी को पहचान लिया है। इसके लिए संघ और भाजपा को स्वयं मे एक बड़े बदलाव की जरूरत है। समय रहते यदि वह बदलाव कर पाते हैं, तभी सत्ता में बने रह सकते हैं।

दतिया के नतीजों से कांग्रेस-भाजपा के दो दिग्गज नेताओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह!

सुरेश तिवारी

दतिया उपचुनाव के नतीजों को लेकर वैसे तो कई परिणाम दूर तक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा परिणाम देखने को मिल रहा है, वह यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के एक-एक दिग्गज नेता के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की अब आगे की राजनीति क्या होगी? सियासी हलकों में चल रही चर्चाओं पर अगर भरोसा किया जाए तो बताया जा रहा है कि नरोत्तम खुद ही अब शांत रहने वाले हैं, लेकिन क्या पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का सोच रही है? इन सबको लेकर चर्चा का दौर गर्म है। इधर, कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की मतगणना के ठीक एक दिन पहले पार्टी ने निष्कासित कर यह संदेश दे दिया कि अब पार्टी में उनके दिन लद गए हैं और पार्टी को उनकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में अब उनका भविष्य क्या होगा यह भी सोचनीय है। वैसे राजनीति में कब कोई फिर सितारा बन जाए, कहा नहीं जा सकता!

दतिया उपचुनाव में भाजपा की पराजय के बाद दिल्ली में लगातार राजनीतिक हलचलें बढ़ी हैं। बताया गया है कि इस हार के बाद प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलाया और उनसे फीडबैक लिया। इधर, पता चला है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के कड़ावर नेता और वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अभी कुछ दिन पूर्व अमित शाह से पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी मुलाकात की थी। इसके बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिल्ली पहुंचे। जानकारों का मानना ​​है कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव और मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव की हार की चर्चा अब वैसे राष्ट्रीय स्तर पर कम हो रही है फिर भी मध्य प्रदेश के सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाओं का दौर चल रहा है। एक पुरानी कहावत है कि जब बुरे दिन आते हैं तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। यह कहावत मध्य प्रदेश वन विकास निगम पर चरितार्थ होती

दिखाई दे रही है। इन दिनों निगम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए कोई भी पीसीसीएफ स्तर का अधिकारी निगम का एमडी नहीं बनना चाहता है। निगम के एमडी के लिए वन बल प्रमुख ने मुख्यालय से जिन पीसीसीएफ के नाम राज्य सरकार के मंत्रालय को भेजे गए हैं उनमें समिता राजौरा, मनोज अग्रवाल और बीएस अत्रागिरी के नाम शामिल हैं। ये सभी वन मुख्यालय में बड़े बजट वाली महत्वपूर्ण शाखा के मुखिया हैं और बताया गया है कि वे वहां से हटना नहीं चाहते हैं। ये सभी निगम के एमडी नहीं बनने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। कोई मंत्री का सहारा ले रहे हैं तो कोई मुख्य सचिव से संबंध होने का फायदा उठाने के प्रयास में हैं। ऐसे में फिलहाल सीसीएफ को निगम के एमडी का प्रभार सौंपा गया है। एचयू खान के 31 जुलाई को रिटायर होने के बाद से निगम के एमडी का पद खाली है।

इंदौर के महावीर पुष्पमित्र भार्गव अपना चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर वरिष्ठ संपादकों से रूबरू हुए। इस दौरान उनके द्वारा बिना किसी लाग लपेट के दिए प्रेजेंटेशन में यह तो स्पष्ट दिखाई दिया कि इंदौर में अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियां तो हासिल की हैं, लेकिन अनेक कार्य वर्ष 2047 की दृष्टि से शुरू किए गए हैं। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि उनके चार साल का कार्यकाल इंदौर के रिवाइवल के रूप में याद किया जाएगा। आने वाला समय बताएगा कि हमने जो काम किए हैं, वह इंदौर की भविष्य की जनसंख्या को देखते हुए उपयोगी साबित होंगे। बता दें, इन दिनों में इंदौर में करीब 23 फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और 22 मास्टर प्लान सड़कों का निर्माण कर रहा है। इसके कारण नागरिकों को कभी-कभी परेशानी भी उठनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तकलीफ जरूर है, लेकिन इसका फायदा आने वाले समय में आपको नजर आएगा। अमृत 2.0 योजना करीब 50 लाख की आबादी को जलप्रदाय के लिहाज से बनाई है। ग्रौन बांड जारी करने वाला इंदौर नगर निगम देश में पहला है। ब्लू बांड की जारी करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बड़वानी पहला आदिवासी जिला है, जहां पंचायत भवनों को नए सिरे से तैयार कर उनका आधुनिकीकरण किया गया है।

मां पार्वती के जल से गणेश का अभिषेक



बुधवार को अच्छी बारिश की कामना को लेकर हजारों महिला-पुरुष पार्वती नदी का जल लेकर चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान का जल से अभिषेक

किया। उसके बाद विधि विधान से पूजा-अर्चना कर अच्छी बारिश, सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की। ज्ञात हो कि हर वर्ष अषाढ के माह में ग्राम पार्वती लोग पार्वती नदी में से जल भरकर व

झंडा लेकर हजारों की तादात में पैदल जत्थे के रूप में सीहोर स्थित चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचते हैं।

इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले दर्जनों गांव के लोग उनका स्वागत कर उनके साथ जत्थे में शामिल हो जाते हैं। यह जत्था पार्वती से शुरू होता है, जिसमें पिपलिया नगर, बाबडिया, खजूरी, मूंडला, कराडिया, बकल, जगनीखेडी, बिजोरा, बिजोरी, नयापुरा, पीलीखेडी, कोडिया, महोडिया सहित दर्जनों ग्राम के लोग शामिल होते हुए चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचते हैं। जहां पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारे का अयोजन किया जाता है।

यह परम्परा कई वर्षों से चली आ रही है, जिसमें सभी ग्रामीण बड़े सद्भाव और सोहाद के साथ हिस्सा लेते हैं, जिसमें बच्चे-बूढ़े, महिला-पुरुष सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं।

राम नाम से ही दूर होते कष्ट

था। त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतरित होकर राक्षसी प्रवृत्तियों का संहार किया था। अपने चरित्र और मर्यादा पालन के कारण श्री राम इस संसार के लिए अनुकरणीय हैं। उन्होंने ब्रहम होकर भी कभी नहीं कहा कि वे ब्रहम हैं। उन्होंने संसार के सामने आदर्श चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत किया और इसलिए वे युगों का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्रीराम की स्तुति हमारे अमंगल का हरण करने वाली और मंगल करने वाली है। श्री राम के नाम की महता के विषय में शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे थे। उन्हें इस तरह बैठा मां पार्वती ने पूछा- प्रभु, सारा

संसार तो आपका ध्यान करता है फिर आप किसके ध्यान में बैठे हैं। तब शिव बोले- मैं राम का स्मरण कर रहा हूं, जिनका नाम ही परम सुखदायक है। वर्णन आता है कि उन्होंने मां पार्वती से कहा- ‘श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे/ सैश्वर्यनामा ततुल्यं राम नाम वरानने। अर्थात हे पार्वती श्रीराम को जपने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।

अभिजीत नक्षत्र में प्रभु राम की अवतरण को सभी जगह उल्लास के साथ मनाया जाता है। विद्वान मानते हैं कि दोहरा 11.45 से 12 तक अभिजीत नक्षत्र रहता है और इसी समय रामनवमी पर प्रभु के प्राकट्य का उत्सव मनाना श्रेयस्कर है। श्रीराम के स्मरण मात्र से ही सभी तरह के क्लेश का नाश हो जाता है। राम रक्षा स्रोत का पाठ असहाय स्थिति में हमारी रक्षा करता है। यह सभी तरह के संकटों से हमें उबारता है।

विविध

भक्तों के कष्ट हरते हैं मंगल मूर्ति मारुति नंदन पवनसुत हनुमान

हनुमान जयंती पवनपुत्र हनुमान के जन्म की प्रसंग तिथि है। हनुमान शिव के ग्यारहवें अवतार के रूप में सर्वत्र पूजनीय हैं। चूंकि शिव भी राम का स्मरण करते हैं इसलिए उनके अवतार हनुमान को भी राम नाम प्रिय है। हनुमान बल और बुद्धि के देव हैं। रामकथा उनके बिना पूरी नहीं होती। वे धर्म में इस शिक्षा के साथ हैं कि अपनी बुद्धि और बल के गर्व से दूर रहते हुए, विनम्र होकर ही संसार का आदर प्राप्त किया जा सकता है। उनका श्रद्धाभाव अतुलनीय है। मंदिरों में हनुमानजी की मूर्ति को पर्वत उठाए और राक्षस का मान मर्दन करते हुए दिखाया जाता है लेकिन राम मंदिरों में वे प्रभु चरणों में मस्तक झुकाए बैठे हैं। वे अनुपम भक्त हैं। हनुमान के संबंध में एक लोककथा है कि एक बार वे माता अंजनी को रामायण सुना रहे थे। उनकी कथा से प्रभावित माता अंजनी ने पूछा, ‘तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम्हारी पूंछ के एक वार से पूरी लंका को उड़ा सकते थे, रावण को मार सकते थे और मां सीता को छुड़ाकर ला सकते हो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया अगर तुम ऐसा करते तो युद्ध

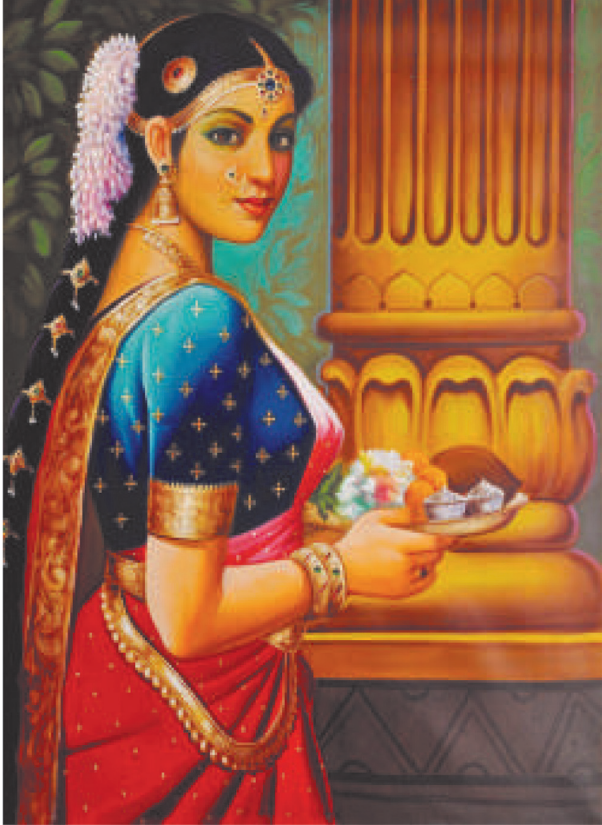
में नष्ट हुआ समय बच जाता हनुमान विनम्रता से कहते हैं, ‘क्योंकि राम ने कभी मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। ‘‘राम के प्रति इस अगाध श्रद्धा के कारण हनुमान पूरे संसार में पूजे जाते हैं। हनुमान जयंती के दिन अगर भक्त 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उनके कष्टों का हरण होता है। हनुमान बाण से सभी तरह के तांत्रिक रोगों का नाश होता है। राम नाम मात्र से ही वे सारे मनोरथ पूरे करते हैं। हनुमान जी को सिंदूर क्यों रामायण में एक कथा प्रसिद्ध है कि हनुमानजी ने जानकी की मांग में सिंदूर लगा देख आश्चर्य से पूछा- माते, आपने यह लाल द्रव्य मस्तक पर क्यों लगाया है। माता जानकी ने हनुमान को इस भोली उत्सुकता पर कहा, ‘पुत्र, इसे लगाने से मेरे स्वामी की रक्षा होती है, वे दीर्घायु होते हैं और वे मुझ पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। हनुमानजी ने यह सुना तो वे बहुत प्रसन्ना हुए और विचार किया कि जब अंगुलीभर सिंदूर से प्रभु की रक्षा होती है तो क्यों न पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर स्वामी को सुरक्षित कर दूं। उन्होंने वैसा ही किया। जब वे इस तरह श्रीराम के सामने पहुंचे तो प्रभु

मुस्कुराए बिना न रह सके। हनुमान का विश्वास मां जानकी के वचनों में पक्का हो गया। तभी से हनुमान को भक्ति का स्मरण करते हुए उन्हें सिंदूर चढाया जाने लगा।

रामकथा सुनते हैं हनुमान माना जाता

हनुमान ने हर एक मोती को दांत से काटकर देखा और पूरी माला तोड़ दी। श्रीराम ने पूछा इतनी सुंदर माला तुमने दांत से काट- काटकर क्यों फेंक दी। हनुमान ने कहा कि प्रभु जिस वस्तु में आप नहीं वह मेरे किस काम की। तब श्रीराम ने पूछा, तुम्हारे हृदय में श्रीराम का निवास है। हनुमान ने हृदय चीरकर दिखाया कि उसमें राम, लक्ष्मण और सीता विद्यमान है। हनुमान को राम नाम प्रिय है। जहां भी रामकथा होती है वहां वे कथा श्रवण आते हैं।

भारतीय संस्कृति में यह व्रत बन चुका है आदर्श नारीत्व का प्रतीक



मूलतः यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का है, फिर भी सभी प्रकार की स्त्रियां (कुमारी, विवाहित,

तक है। इस दिन वट (बड़, बरगद) का पूजन होता है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत माना गया है।

भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक बन चुका है। इस व्रत की तिथि को लेकर भिन्न मत हैं। स्कंद पुराण तथा भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत करने का विधान है, वहीं निर्णयामृत आदि के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को व्रत करने की बात कही गई है।

व्रत का विधान प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर बांस की टोकरी में रेत भर कर ब्रहमाजी की मूर्ति की स्थापना करें। ब्रहमाजी के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान की मूर्तियों को स्थापना करके टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखना चाहिए।

जैन धर्म की व्यापकता और दर्शन का श्रेय भगवान महावीर को

लगभग 2500 वर्ष पहले अहिंसा और सहिष्णुता की शिक्षा देने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जीवन ही उनका संदेश है। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत और आदर्श वर्तमान संदर्भों में और सभी के लिए प्रासंगिक हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रहमचर्य और अस्तेय आदि अनेक उपदेशों को अपनाकर आज भी रामराज्य की स्थापना की जा सकती है। वर्धमान महावीर का जन्मन्दिन महावीर जयंती के रुप में मनाया जाता है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान आदिनाथ की परंपरा में चौबीस वें तीर्थंकर हुए थे और उनका जीवन काल 511 से 527 ईस्वी ईसा पूर्व तक माना जाता है। उनका जन्म बिहार के कुंडलपुर में हुआ था। महावीर के पिता का नाम राजा सिद्धार्थ एवं माता का नाम रानी त्रिसला था। उनका जन्म हन्दू कैलेंडर के चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ था। पावापुर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। भगवान महावीर कठोर तप से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर जिन अर्थात विजेता कहलाए। उनका यह कठिन तप पराक्रम के सामन माना गया और इस वजह से उन्हें महावीर कहा गया तथा उनके अनुयायी जैन

कहलाए। जैन धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के आरंभ किए तत्वज्ञान को परिभाषित करके जैन दर्शन को स्थायी आधार दिया। उन्होंने श्रद्धा एवं विश्वास के जरिए जैन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। इसीलिए आधुनिक काल में जैन धर्म की व्यापकता और उसके दर्शन का श्रेय महावीर स्वामी को दिया जाता है। महावीर स्वामी को अर्हत, जिन, निग्रथं, अतिवीर आदि नामों से भी जाना जाता है। उन्होंने लोगों को जिओ और जीने दो के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने घोर तपस्या से अपनी इंद्रिय पर विजय हासिल की ली थी। इस पर्व को तप से जीवन पर विजय प्राप्त करने का पर्व भी कहा जाता है। भगवान महावीर के समय में समाज व धर्म में अनेक विषमताएं थी। ऐसे में उन्होंने आडंबरों से घिरे धर्म और अत्याचार से पीडित समाज को नवजीवन दिया। उन्होंने कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करने के साथ धर्म की वास्तविकता को



स्थापित कर सत्य एवं अहिंसा पर बल दिया। भगवान महावीर के सिद्धांतों में अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, आत्म स्वातंत्र्य शामिल है।

उपदेशों से समाज कल्याण महावीर जी ने अपने उपदेशों द्वारा समाज का कल्याण किया। उनकी शिक्षाओं में मुख्य बातें थी कि सत्य का पालन करो, अहिंसा को अपनाओ, जिओ और जीने दो। इसके अतिरिक्त उन्होंने पांच महाव्रत, पांच अनुव्रत, पांच समिति, तथा छः आवश्यक नियमों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। जो जैन धर्म के प्रमुख आधार हुए उन्होंने लोक कल्याण का मार्ग अपने आचार-विचार में लाकर धर्म प्रचारक का कार्य किया।

इसीलिए कहते हैं तुलसी को विष्णु-प्रिया

कार्तिक शुक्ल की एकादशी को तुलसी पूजन का विधान है। इस वर्ष यह पर्व 3 नवंबर को है। तुलसी पूजन का पर्व पूरे उत्तर भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तुलसी को विष्णु-प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी का पौधा भारतीयों के लिए गंगा-यमुना के समान पवित्र है।

व्रत की कथा प्राचीन काल में जालंधर नाम का दैत्य था। उसने सारे संसार में उत्पात मचा रखा था। दैत्य की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म। कहा जाता है कि उसी के प्रभाव से वह विजेता बनता था। दैत्य के उत्पत्ति से परेशान होकर ऋषि-मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने काफी सोच विचार कर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने योगमाया द्वारा एक मृत शरीर वृंदा के घर के बाहर

फिकवा दिया। माया का पर्दा होने से वृंदा को अपने पति का शव दिखाई दिया। अपने पति को मृत

जानकर वह उस मृत शरीर पर गिरकर विलाप करने लगी। उसी समय एक साधु उसके पास आए और कहने

लगे बेटी इतना विलाप मत करो। मैं इस मृत शरीर में जान डाल देता हूं। साधु ने मृत शरीर में जान डाल दी। भावों में बहकर वृंदा ने उस शरीर का आलिंगन कर लिया। बाद में वृंदा को पता चला कि यह तो

उसका पति देवताओं से युद्ध कर रहा था और वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही वह देवताओं द्वारा मारा गया। इस बात का जब वृंदा को पता चला तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि, जिस प्रकार आपने छल से मुझे पति वियोग दिया है।

उसी तरह आपको भी स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्युलोक में जन्म देना होगा। यह कहकर वृंदा अपने पति की अर्थी के साथ सती हो गई। विष्णु अब अपने छल पर बड़े लज्जित हुए। माता पार्वती ने वृंदा की चिंता-भस्म में आंवला, मालती व तुलसी के पौधे लगाए। भगवान विष्णु ने तुलसी को ही वृंदा का रूप समझा।

इस घटना के बाद त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया और सीता के वियोग में कुछ दिनों तक रहना पड़ा।

2017-18 को छोड़ 2080 तक 15 को ही संक्रांति

उज्जैन के पंचांग विशेषज्ञों के अनुसार मकर संक्रांति करीब 100 साल बाद इस बार 15 जनवरी को मनाई जा रही है। वजह यह है कि पृथ्वी हर साल 50 विकला (यानी 20 मिनट) पीछे रह जाती है। 65 से 100 साल के बीच यह अंतर 24 घंटे का हो जाता है। यही वजह है कि अब 2080 तक संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी।

लीप ईयर के कारण दो साल क्रम बदलेगा और 2017-18 को संक्रांति फिर 14 जनवरी को होगी, क्योंकि साल के दिन घटने से सूर्य पुरानी स्थिति में आ जाएगा। दिन बड़े क्यों गणना के अनुसार संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं,

इस कारण दिन बड़े होने लगते हैं। हालांकि वैज्ञानिक तर्क है कि 21 दिसंबर से दिन बड़ा और रात छोटी होने लगती है।

पौराणिक मान्यता महाभारत युद्ध में घायल भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के बाद शरीर त्यागा था। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्मा कुछ काल के लिए देवलोक चली जाती है या उसे जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है।

गंगा का अवतरण संक्रांति के दिन ही गंगा नदी का अवतरण धरती पर हुआ। इसलिए इस दिन को पावन माना जाता है। इसका संबंध ऋतु परिवर्तन से भी है। संक्रांति से तापमान बढ़ने लगता

है। आहार विशेषज्ञों के मुताबिक तिल-गुड़ में कैल्शियम और आयरन होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ स्टेमिना भी बढ़ाता है। धार्मिक महत्व तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से मानी जाती है, जबकि गुड़ खाने से शनि प्रसन्न होते हैं। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर का स्वामी शनि है। तिल-गुड़ खाने से सूर्य नारायण व शनि की खुशी प्राप्त होती है।

संक्रांति के मुहूर्त विशेष पुण्यकालः सूर्योदय (7.10) से सुबह 11.27 बजे तक। सामान्य पुण्यकालः सूर्योदय (7.10) से सूर्यास्त (शाम 6.00) तक।

परिस्थितियां बदलती हैं हमेशा

एक बार भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे। वह पैदल यात्रा कर रहे थे, इस कारण थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके साथ उनके अन्य शिष्यों के साथ आनंद भी मौजूद थे। भगवान बुद्ध ने कहा, ‘आनंद यहां नजदीक एक झरना है, वहां से जल ले आओ।’ आनंद झरने के पास पहुंचा, लेकिन वहां गंदा पानी बह रहा था। उन्होंने पानी भरना ठीक नहीं समझा। वह थोड़ा देर रुके और पानी साफहो गया। उन्होंने साफपानी कमंडल में भरा। और बुद्ध के पास चल दिए। उन्होंने सारा घटनाक्रम तथागत को सुनाया। तब बुद्ध ने कहा, ‘आनंद प्रकृति को देखो, परिस्थिति को नहीं। परिस्थिति बदल जाती है, लेकिन प्रकृति स्थिर रहती है। जैसा कि तुमने देखा किस तरह झरने का गंदा जल थोड़ी देर बाद स्वच्छ हो गया।’

संक्षेप में‘मनुष्य की भी यही स्थिति है। झरने के पानी की तरह मनुष्य भी बदलता है। मनुष्य हमेशा अपने स्वभाव के अनुरूप वहीं नहीं रहता बल्कि वह बदलता है। यही सनातन नियम है।

सीजेआई से डिग्री नहीं लेंगे ‘काँकरोच’

नईदिल्ली। हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में कान्वोकेशन सरेमनी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. यूनिवर्सिटी ने समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है, जिसका यूनिवर्सिटी के पास आउट हो रहे छात्रों के एक समूह ने विरोध किया है। छात्रों के समूह ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, कुलसचिव, फैकल्टी और प्रशासन को पत्र लिखकर मुख्य अतिथि के तौर पर सीजेआई सूर्यकांत को आमंत्रित करने के फैसले पर पुर्नविचार करने की मांग की है. पत्र में छात्रों ने हालिया घटनाक्रमों का हवाला देते हुए कहा कि सीजेआई को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना संवैधानिक जवाबदेही और शैक्षणिक स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को लेकर सवाल खड़े करता है. विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजे गए पत्र में छात्रों ने लिखा, युवाओं को ‘कांकरोच’ कहने से लेकर पुलिस बर्बरता के वीडियो देखने का समय न होने जैसी असंवैदनाशील टिप्पणियों तक, सीजेआई ने हमारे जैसे छात्रों के प्रति उदासीनता दिखाई है।

भारत बनाएगा 6th जेनरेशन फाइटर जेट

नईदिल्ली। भारत की रक्षा तैयारियों में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ चुका है. रक्षा मंत्रालय ने संसदीय स्थाई समिति को बताया है कि वह फ्रांस सरकार के नेतृत्व वाले छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकास कार्यक्रम यानी पयूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम या स्रष्ट्र में शामिल होने के लिए ठोस और समन्वित प्रयास शुरू कर चुका है. साथ ही ब्रिटेन, इटली और जापान के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी तक्षक का भी मूल्यांकन जारी है. यह कदम भारत की वायु शक्ति को 2040 के दशक तक मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया है, जहां आधुनिक खतरे तेजी से बदल रहे हैं. छठी पीढ़ी के सिस्टम में स्टील्थ तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फैसले, लॉयल विंगमैन ड्रोन और नेटवर्क आधारित युद्ध की क्षमताएं शामिल हैं. ये भविष्य की लड़ाई को दल देंगी.एफसीएएस की शुरुआत 2017 में फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी. बाद में स्पेन भी जुड़ गया।

चीन की पैतरेबाजी को भारत का करारा जवाब

नईदिल्ली। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक नक्शे में 27 स्थानों को शामिल किया है, जिनमें थग ला पास, लॉन्गजू और शेर-ए-थापा मेमोरियल शामिल हैं. यह चीन के दावों का जवाब है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले महत्वपूर्ण है.भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक सर्वे ऑफ इंडिया नक्शे को अपडेट किया है. इसमें चीन की सीमा से जुड़े रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पास, झीलें, बस्तियां और एक युद्ध स्मारक शामिल किए गए हैं. कुल 27 स्थानों को मानक भारतीय नामों के साथ औपचारिक रूप से चिह्नित किया गया है. यह कदम चीन की ओर से अरुणाचल को जंगनान या दक्षिण तिब्बत कहकर बार-बार नाम बदलने के प्रयासों के जवाब में आया है. भारत हमेशा से कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है. नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती. यह अपडेट उस समय हुआ है।

एफसीआरए बिल को कांग्रेस ने बताया एंटी क्रिश्चियन

नईदिल्ली।संसद का मानसून सत्र इस समय चल रहा है. इस बीच चर्चा है कि सरकार इस सत्र में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन करने के लिए नया बिल ला सकती है. कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का पुरजोर विरोध करने का मन बना लिया है. कांग्रेस का कहना है कि यह बिल ईसाई विरोधी है. इस बिल से देश में काम कर रहे अल्पसंख्यक संगठनों को बहुत नुकसान होगा. कांग्रेस नेताओं का मानना है कि एफसीआरए के नए नियमों से देश के दूर-दराज, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में चल रहे ईसाई संगठनों, स्कूलों और अस्पतालों पर बुरा असर पड़ेगा. कांग्रेस सांसद हिबी इंडन का कहना है कि देश के कई मुश्किल इलाकों में ये संगठन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं. लेकिन, सरकार इन्हें दबाना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि नए बिल के नियमों के तहत जिला मजिस्ट्रेट या उप-जिला मजिस्ट्रेट नियमों के उल्लंघन पर किसी भी संस्था की संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकते हैं।

भागवत के बयान पर भड़कीं मायावती

लखनऊ। बसपा सुप्रिमी मायावती ने रविवार को ‘X’ पर पोस्ट कर आरक्षण की वकालत की. उन्होंने क्रस् से आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील की. उन्होंने आरक्षण खत्म करने की कोशिश को बाबासाहब अंबेडकर के उद्देश्यों के खिलाफ बताया.उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इसे देखते हुए समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं. बसपा सुप्रिमी मायावती ने रविवार को ‘X’ पर पोस्ट कर आरक्षण का समर्थन किया. आरक्षण में क्रीमि लेयर लाए जाने को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि यह बाबासाहब अंबेडकर के उद्देश्यों के खिलाफ है. साथ ही, उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी सोच संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है. बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि एस्सी, एसटीऔर ,ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण बेहद संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि इन समुदायों ने लंबे समय तक जाति के आधार पर भेदभाव झेला है।

पहली बार लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा वंदे मातरम स्वतंत्रता दिवस 2026

नईदिल्ली। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। इस समारोह की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह मौका %बंदे मातरम% के 150 साल पूरे होने का भी प्रतीक होगा। पीएम मोदी दिल्ली के इस ऐतिहासिक स्मारक से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। बयान में कहा गया, पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा।

इस साल का समारोह युवा शक्ति पर केंद्रित होगा, जिसमें 2047 तक विकसित भारत बनने



की देश की यात्रा में भारत की युवा आबादी के योगदान को उजागर किया जाएगा। राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान के समान कानूनी दर्जा: संसद ने हाल ही में %राष्ट्रीय सम्मान के अपमान को रोकथाम (संशोधन) विधेयक पारित किया है। इसके तहत वंदे मातरम को अपमानजनक कृत्यों के कानूनी सुरक्षा दी गई है और राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान के समान कानूनी दर्जा दिया गया है।

इस कानून को लेकर लोकसभा में थोड़ी देर के लिए राजनीतिक बहस भी हुई। डीएमके ने इसका विरोध किया और सरकार पर राष्ट्रीय गीत का इस्तेमाल देश को बांटने के लिए करने का आरोप लगाया।हालांकि, बीजेपी ने इस संशोधन का बचाव करते हुए कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि नागरिक बिना किसी बाधा के वंदे मातरम के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकें।

विपक्षी दलों ने किया संसद भवन परिसर में प्रदर्शन

नईदिल्ली।छात्रों के साथ पुलिस कार्रवाई तथा चढ़ावा चोरी सहित कई मुद्दों पर विपक्षी दलों के सांसदों ने सोमवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए।

विपक्षी सांसदों ने हाथों में तखियां और बैनर लेकर विरोध जताया। तखियों पर गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीर भी थी,



जिन पर संसद में उनकी अनुपस्थिति को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई थी।

प्रदर्शनकारियों में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी,

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल तथा प्रियंका गांधी वाड़ा शामिल कांग्रेस के अन्य कई सांसद शामिल थे।

संसद भवन परिसर में कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी तथा शिवसेना उद्धव गुट के साथ ही कई अन्य दलों के सांसद भी शामिल थे।

सेंसेक्स 43 अंक चढ़ा निफ्टी 24,584 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को पूरे कारोबारी सत्र के दौरान सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। स्ट्रेट ऑफ होमर्ज को खोलने को लेकर अनिश्चितता के बीच निफ्टी50 और सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में निफ्टी50 13.15 अंक यानी 0.05% की बढ़त के साथ 24,583.80 पर बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स 43.27 अंक यानी 0.06% चढ़कर 78,542.44 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी50 में स्ट्रेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी और Etemal के शेयर सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे। वहीं, व्यापक बाजार की बात करें तो निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.62% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मालकैप में 0.27% की गिरावट रही। सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 2% टूट गया और दिन का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा।

57 अरब डॉलर निकालने के बाद बदला विदेशी निवेशकों का रुख

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार से लंबे समय से दूरी बना रहे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का रुख आखिरकार जुलाई 2026 में बदलता नजर आया। लगातार चार महीने को तेज बिकवाली के बाद FII जुलाई में भारतीय शेयरों के शुद्ध खरीदार बने और उन्होंने 2.5 अरब डॉलर का निवेश किया। यह पिछले 13 महीनों में सबसे ज्यादा मासिक विदेशी निवेश है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट में कहा कि FII को यह वापसी ऐसे समय हुई है जब कंपनियों की कमाई में सुधार, वैल्यूएशन में नरमी और ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव कम होने से भारत का निवेश आउटलुक बेहतर होता दिख रहा है। आगे विदेशी निवेश की रफ्तार काफी हद तक भू-राजनीतिक हालात, कच्चे तेल की कीमतों, वैश्विक बॉन्ड यील्ड और ङु आधारित वैश्विक तेजी के रुख पर निर्भर करेगी।

डीएलएफ ने आवासीय परियोजना में 271 करोड़ रु. में बेचा पेंटहाउस

नई दिल्ली। रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी डीएलएफ लिमिटेड ने गुरुग्राम स्थित अपनी आगामी लक्जरी आवासीय परियोजना में 271 करोड़ रुपए में एक पेंटहाउस बेचा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, प्रति वर्ग फुट कीमत के लिहाज से यह देश के सबसे महंगे सौदों में से एक है। डीएलएफ ने अक्टूबर, 2024 में गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-5 में 17 एकड़ में फैली अपनी लक्जरी आवासीय परियोजना द डहलियाज शुरू की थी। इस परियोजना में 420 अपार्टमेंट और पेंटहाउस शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने इस परियोजना का एक पेंटहाउस उद्यमी मानव सरदाना को बेचा है। सूत्रों के अनुसार, सुपर एरिया के आधार पर डीएलएफ ने यह पेंटहाउस 1.58 लाख रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से बेचा है, जबकि कारपेट एरिया के हिसाब से इसकी बिक्री कीमत करीब 2.6 लाख रुपए प्रति वर्ग फुट बैठती है।

सीएनएच इंडिया की ट्रैक्टर बिक्री 42 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली। कृषि उपकरण विनिर्माता कंपनी सीएनएच की भारतीय इकाई ने वर्ष 2026 की पहली छमाही में घरेलू बाजार में 30,248 ट्रैक्टर बेचे। यह एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान कंपनी की भारत में बाजार हिस्सेदारी भी अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सीएनएच इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नरेंद्र मि्तल ने कहा कि 2026 की जनवरी-जून अवधि के दौरान कंपनी का ट्रैक्टर निर्यात करीब 20 प्रतिशत बढ़कर 6,666 वाहन हो गया। उन्होंने कहा कि वर्ष की शुरुआत में अमेरिकी शुल्क से कुछ समय के लिए बाधा आई थी लेकिन बाद में स्थिति सामान्य होने पर निर्यात में फिर तेजी आई। कंपनी भारत में न्यू हॉलैंड और केस आईएच ब्रांड के तहत कारोबार करती है।

आ गई बुरी खबर! भारत पर फूटने ही वाला है ट्रंप का ये खतरनाक बम

अभिनय आकाश भारत पर 100 % टैरिफ वाला बिल, यूएस सेनट से पारित हुआ है। भारत समेत 5 देश ऐसे हैं, जहां पर 100% टैरिफ वाला बिल, यूएस में पास हो गया है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ से बचने के लिए यूएस लगाएगा। 31 अगस्त को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रखा जाएगा, लेकिन अमेरिकी सीनेट से ये पारित हो गया है। 86 जो सीनेट के सदस्य हैं, यानि संसद उन्हों ने इसके समर्थन में वोट किया। इसके पारित होने के बाद पांच देशों के खिलाफ 100% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। हालांकि कि ये पूरा अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को होगा, लेकिन अगर ये बिल पारित हो जाता है, तो भारत और वैसे देश जो रूस से सबसे अधिक मात्रा में तेल आयात करते हैं, उन पर संकट पैदा हो सकता है। लेकिन ये पूरा अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति

डोनाल्ड ट्रंप को होगा, लेकिन भारत के लिए ये ऐसा बिल है, जो आने वाले वक्त में भारत को मुश्किलों में डाल सकते हैं। अमेरिकी सेनेट ने 86-11 के भारी बहुमत से लिंडसे ओ. ग्राहम संक्शांनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 पारित किया है। इस द्विपक्षीय विधेयक का नाम दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है, जो इसके मुख्य वास्तुकारों में से एक थे। बिल का मुख्य उद्देश्य रूस और ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और उन देशों पर शिकजा कसना जो माँस्को (रूस) के साथ बड़े पैमाने पर ऊर्जा व्यापार जारी रखे हुए हैं। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों से आयात होने वाले सामानों पर 100% तक का सीमा शुल्क लगाने का अधिकार देता है, जो रूसी तेल या प्राकृतिक गैस के दुनिया के शीर्ष 5 खरीदारों में शामिल हैं।

यह विधेयक सिर्फ रूसी तेल खरीदारों के बीच ही फैल रहा है, जो आने वाले वक्त में भारत को मुश्किलों में डाल सकते हैं। अमेरिकी सेनेट ने 86-11 के भारी बहुमत से लिंडसे ओ. ग्राहम संक्शांनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 पारित किया है। इस द्विपक्षीय विधेयक का नाम दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है, जो इसके मुख्य वास्तुकारों में से एक थे। बिल का मुख्य उद्देश्य रूस और ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और उन देशों पर शिकजा कसना जो माँस्को (रूस) के साथ बड़े पैमाने पर ऊर्जा व्यापार जारी रखे हुए हैं। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों से आयात होने वाले सामानों पर 100% तक का सीमा शुल्क लगाने का अधिकार देता है, जो रूसी तेल या प्राकृतिक गैस के दुनिया के शीर्ष 5 खरीदारों में शामिल हैं।



पर शुल्क लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अन्य कठोर प्रतिबंध शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों, और कुलीन वर्गों पर सीधे प्रतिबंध। रूस के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और युद्ध प्रयासों को वित्तपोषित करने वाली संस्थाओं पर पाबंदी। रूस द्वारा मौजूदा प्रतिबंधों से बचने और तेल निर्यात से कमाई जारी रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने और दूसरे देशों के झंडे वाले तेल टैंकरों पर प्रतिबंधों का विस्तार। इसके तहत ईरान के ऊर्जा और हथियार क्षेत्रों

पर प्रतिबंधों को आगे बढ़ाया गया है। रूस की अर्थव्यवस्था और उसके सैन्य अभियान को मिलने वाली फंडिंग को रोकना। यदि यह विधेयक पूरी तरह से कानून बनता है, तो राष्ट्रपति के पास शीर्ष 5 रूसी तेल खरीदारों से अमेरिका को तेल देने वाले सामानों पर 100% शुल्क लगाने की शक्ति होगी। भारत और चीन दुनिया में रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं। इस कानून की संरचना ऐसे की गई है कि देशों को अमेरिका के साथ व्यापार बनाए रखने और रूस से सस्ता तेल खरीदने में से किसी एक को चुनना पड़े। डालाइन ग्राहम (दिवंगत सीनेटर की बहन) ने कहा कि यह विधेयक रूस की अर्थव्यवस्था को संभाले रखने वाले प्रमुख देशों को एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण विकल्प चुनने के लिए मजबूर करता है- अमेरिका के साथ व्यापार करने का विकल्प या रूस से सस्ता तेल खरीदने का विकल्प। 2022 में

रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चा तेल खरीदना काफी बढ़ा दिया है। रूस पहले भारत के लिए तेल का कोई बड़ा सप्लायर नहीं था, लेकिन माँस्को और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने और यूरोप द्वारा रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद करने के बाद, यह भारत के लिए भारी छूट पर उपलब्ध हो गया। इस बदलाव से भारतीय रिफाइनरों को कच्चे तेल की लागत कम करने और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में रुकावटों के बावजूद सप्लाई सुनिश्चित करने में मदद मिली है। होर्मुज जलडमरूमध्य से शिपिंग में रुकावटों के बीच रूसी तेल पर निर्भरता और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इन रुकावटों ने मध्य पूर्व से ऊर्जा को सप्लाई को प्रभावित किया है। नई दिल्ली ने बार-बार कहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित, ऊर्जा सुरक्षा और किफायती व भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित करने की ज़रूरत से तय होती है।



विश्वास, विकास और जनकल्याण का नया अध्याय

हर घर तक सुविधाएं, हर हाथ को अवसर हर चेहरे पर संतोष की मुस्कान

वर्ष 2026 का छत्तीसगढ़ एक ऐसे परिवर्तन का साक्षी बन रहा है, जहां विकास केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में दिखाई देता है। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, स्कूल से अस्पताल तक और सरकारी दफ्तरों से डिजिटल सेवाओं तक—हर क्षेत्र में बदलाव की एक नई तस्वीर उभरकर सामने आई है। खाद्य सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सुशासन, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हुए व्यापक कार्यों ने प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज छत्तीसगढ़ में विकास का अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। यही कारण है कि प्रदेश में करोड़ों लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली जनहितकारी पहलें सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का मजबूत आधार बन रही हैं।

छत्तीसगढ़ का विकास केवल निर्माण कार्यों या आंकड़ों तक सीमित नहीं है। हमारा लक्ष्य ऐसा प्रदेश बनाना है जहां हर परिवार सुरक्षित, हर युवा आत्मनिर्भर, हर किसान समृद्ध, हर महिला सशक्त और हर नागरिक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। जनकल्याण, सुशासन, पारदर्शिता और विकास को केंद्र में रखकर हम नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तकनीक, सेवा और संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

—विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

गरीब की थाली में सम्मान, हर परिवार को खाद्य सुरक्षा का भरोसा



खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने देशभर में एक अलग पहचान बनाई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करोड़ों हितग्राहियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था लगातार मजबूत हुई है। राशन दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तकनीक आधारित निगरानी, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और डिजिटल सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं ने वितरण प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाया है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न की नियमित उपलब्धता ने न केवल उनकी आर्थिक चिंता कम की है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत आधार प्रदान किया है। दूरस्थ और आदिवासी अंचलों तक खाद्य सामग्री की सुगम आपूर्ति ने प्रदेश की समावेशी विकास नीति को और सशक्त किया है।

किसानों के जीवन में खुशहाली, खेती को मिला नई ऊर्जा का आधार



छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और किसानों की समृद्धि को विकास का केंद्र माना गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग तथा कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ-साथ पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन और लघु वनोपज आधारित गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिला है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्राप्त हुई है और रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी सृजित हुए हैं।

युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर



प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेले, मॉडल करियर सेंटर, कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्योगों से समन्वय और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से व्यापक पहल की गई है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया है। रोजगार कार्यालयों के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को बेहतर सुविधा मिली है। वहीं स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं ने हजारों युवाओं को नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाला बनने का अवसर प्रदान किया है।

महिलाएं बन रही हैं विकास की मजबूत भागीदार



महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, विपणन अवसर और स्वरोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्व-सहायता समूहों की सफलता ने महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक और आर्थिक निर्णयों में अधिक भागीदारी का अवसर भी प्रदान किया है। आज प्रदेश की हजारों महिलाएं अपने परिवार और समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

डिजिटल तकनीक से सुशासन को नई गति



सेवा सेतु, ऑनलाइन नागरिक सेवाएं, डिजिटल भुगतान, ई-ऑफिस, भारतनेट और तकनीक आधारित प्रशासनिक सुधारों ने शासन और जनता के बीच की दूरी को कम किया है। अब अनेक सरकारी सेवाएं लोगों को घर बैठे उपलब्ध हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और शासकीय सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विस्तार ने पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूत किया है। तकनीक आधारित प्रशासन ने सेवा वितरण को तेज, सरल और प्रभावी बनाया है।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, बेहतर इलाज की बढ़ती पहुंच



प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए अस्पतालों का उन्नयन, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता तथा विशेषज्ञ सेवाओं को बढ़ावा दिया गया है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन से स्वास्थ्य संकेतकों में सकारात्मक सुधार देखने को मिला है।

शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं



स्कूलों के उन्नयन, डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट कक्षाओं, छात्र हितैषी योजनाओं और उच्च शिक्षा के विस्तार ने प्रदेश के विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शैक्षणिक अंतर कम करने की दिशा में किए गए प्रयासों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ी है। तकनीक आधारित शिक्षा ने विद्यार्थियों को आधुनिक ज्ञान और कौशल से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सड़क, बिजली, पानी और अधोसंरचना से बदली विकास की तस्वीर



सड़क निर्माण, पुल-पुलियों, पेयजल योजनाओं, विद्युत आपूर्ति और शहरी विकास परियोजनाओं ने प्रदेश की आधारभूत संरचना को नई मजबूती प्रदान की है। गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने, परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने और बुनियादी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने से लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है। इससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिली है।

आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई रोशनी



दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर में सुधार के लिए विशेष प्रयासों ने समावेशी विकास की अवधारणा को और मजबूत किया है। गांवों में सुविधाओं का विस्तार सामाजिक परिवर्तन की नई कहानी लिख रहा है।

संवाद-48628/1

विकास की रफ्तार / जनकल्याण का विस्तार / सुशासन का विश्वास

यही है नया छत्तीसगढ़—जहां विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है और जनकल्याण की योजनाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।